● वर्ष-5

● अंक-256

रायपुर, शुक्रवार
12 जून 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› ई-एचआरएमएस पोर्टल से रखी...

नीति आयोग में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को दिया विकास का मंत्र

विकसित भारत 2047 के लिए बनाया गया मास्टर प्लान

नईदिल्ली। नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर में भी भारत की मजबूत विकास यात्रा पर भरोसा जताते हुए कहा कि देश आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, सहयोग और साझा जिम्मेदारी बेहद आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सहकारी संघवाद की भावना ही भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

हम आपको बता दें कि नयी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित संस्कृति केंद्र में आयोजित इस बैठक का मुख्य विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया, जिसके अंतर्गत देश के हर नागरिक के विकास, सम्मान और समान अवसरों पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में देशभर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए तथा समावेशी मानव विकास ढांचे के चार प्रमुख स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें बुनियादी मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार और उद्यमिता, स्वास्थ्य तथा पोषण और सभी के लिए समानता एवं गरिमा जैसे विषय शामिल रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभ देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और इसे गंवाया नहीं जा सकता। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मांग आधारित कौशल विकास

और व्यापक रोजगार अवसरों का निर्माण सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्त युवा ही भारत की विकास यात्रा को नई गति देंगे। बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिनसे निर्यात और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन और गुणवत्ता सुधार के माध्यम से भारतीय उद्योग विश्व बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना सकते हैं।

महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व वाला विकास विकसित भारत की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि खेती, नवाचार, विज्ञान, उद्योग और नवउद्यम जैसे क्षेत्रों में नारी शक्ति का योगदान लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। उनका कहना था कि महिलाओं की पूरी क्षमता का उपयोग किए बिना भारत का समग्र विकास संभव नहीं है। बैठक में शासन व्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी को विकास के प्रमुख साधन के रूप में रेखांकित किया गया। साथ ही जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली पर भी बल दिया गया ताकि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। शासी परिषद ने दिसंबर 2025 में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार किया।

हम आपको यह भी बता दें कि वैसे तो बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आये लेकिन कर्नाटक के नये मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से पिछले कुछ वर्षों में नीति आयोग की बैठकों से दूरी बनाए रखने की परंपरा के विपरीत शिवकुमार ने इस बार बैठक में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें सहयोग का भरोसा दिया था और राज्य के हित में केंद्र के साथ मिलकर काम किया जाएगा। शिवकुमार ने बैठक में कर्नाटक की आवश्यकताओं और विकास योजनाओं को मजबूती से रखा। उन्होंने बेंगलुरु को देश की आर्थिक और तकनीकी शक्ति बताते हुए कहा कि दुनिया भारत को बेंगलुरु के माध्यम से देख रही है। उन्होंने राज्य में आधारभूत ढांचे, शहरी परिवहन और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इसके अलावा, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपालों ने अपने अपने राज्य से संबंधित मांगें और सुझाव बैठक के दौरान रखे साथ ही अपनी उपलब्धियों का विवरण भी प्रस्तुत किया। हम आपको बता दें कि आमतौर पर, इस परिषद की बैठक हर साल होती है। पिछले वर्ष यह 24 मई को आयोजित की गई थी

रायपुर । अपना पक्का घर हर परिवार का सपना होता है। बालोद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इस सपने को तेजी से साकार कर रही है। सुशासन तिहार 2026 के दौरान बालोद जिले में आयोजित समाधान शिविरों में जब जनप्रतिनिधियों ने आवास लाभार्थियों को उनके नए घरों की 'खुशियों की चाबी' सौंपी, तो अनेक परिवारों की वर्षों पुरानी आकांक्षा पूरी होने की खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक उठी।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत 54,151 आवासों में से 48,421 आवास पूर्ण हो चुके हैं। यह कुल लक्ष्य का 89.42 प्रतिशत है। शेष 5,730 आवास निर्माणाधीन हैं।

मॉनसून तेज चाल से पहुंचा बिहार,यूपी-छत्तीसगढ़, झारखंड की ओर बढ़ा

नई दिल्ली। देश में मॉनसून अब पूर्वी राज्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है. दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने के बाद अब वो बिहार भी पहुंच चुका है. एक हफ्ते में दक्षिणपश्चिम मॉनसून 16 राज्यों पर छा गया है. 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद से वो लगातार आगे बढ़ रहा है. अब उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ओर मॉनसून ने रुख कर लिया है. अगले 2-3 दिनों में इन राज्यों में भी मॉनसून की दस्तक के साथ बारिश हो सकती है. एक हफ्ते में मॉनसून की चाल अनुकूल रही है.

दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से

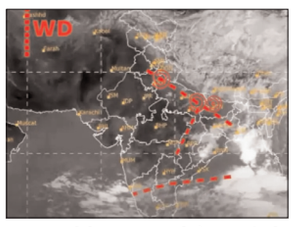

बारिश होने का अलर्ट है. दिल्ली में भी 11-12 जून को झमाझम बारिश होने का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण बारिश आने का संकेत है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक हफ्ते के दौरान उत्तर भारत में बारिश, बिजली गिरने, ओले गिरने और आंधी का मौसम रहेगा. पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 4-5 दिनों के दौरान बरसात हो सकती है।

राज्यसभा की 21 सीटों पर निर्विरोध चुनाव में भाजपा के 12, कांग्रेस के चार उम्मीदवार निर्वाचित

नयी दिल्ली। देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे द्विवार्षिक चुनाव में 21 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं। इसके अलावा तीन राज्यों की तीन राज्यसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

झारखंड की दो तथा मिजोरम की एक सीट पर 18 जून को मतदान होगा। झारखंड की दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा तथा भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी शामिल हैं। वहीं मिजोरम की एक सीट के लिए एमएनएफ के निवर्तमान सदस्य के. वनलालवेना और जेडपीएम समर्थित लालह्मिंगलियाना चुनाव मैदान में हैं।राज्यसभा की जिन 21 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उनके लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि गुरुवार थी। आठ राज्यों की 21 सीटों के लिए 21 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए और उनके विरुद्ध कोई अन्य प्रत्याशी मैदान में नहीं होने के कारण उन्हें

निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

मध्य प्रदेश में तीन सीटों के लिए चार उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के बाद तीन सीटों के लिए केवल तीन उम्मीदवार ही शेष बचे। इसके मद्देनजर तीनों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। सुश्री नटराजन ने नामांकन पत्र रद्द किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। निर्विरोध निर्वाचित 21 उम्मीदवारों में भाजपा के 12, कांग्रेस के चार, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के तीन, जनसेना पार्टी का एक तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) का एक उम्मीदवार शामिल है।

प्रमुख समाचार

टीएमसी को झटका, राज्यसभा सांसद बारिक ने दिया इस्तीफा

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर छिड़ा आंतरिक विद्रोह अब पूरी तरह बेकाबू होता नजर आ रहा है। गुरुवार को पार्टी को एक और करारा झटका लगा जब राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बारिक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार, बारिक ने

राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। पिछले महज एक हफ्ते के भीतर संसद से इस्तीफा देने वाले वे टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद हैं। बारिक से पहले सोमवार को दिग्गज नेता सुखेंदु शेखर रॉय और बुधवार को सुष्मिता देव ने अपने पदों से इस्तीफा देकर टीएमसी नेतृत्व को हिलाकर रख दिया था। बारिक के इस्तीफ़े के साथ, राज्यसभा में पार्टी की संख्या घटकर 10 सांसद रह जाएगी। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि अगले हफ़्ते के अंदर टीएमसी के तीन और राज्यसभा सांसद इस्तीफ़ा दे सकते हैं, जिससे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए संकट और गहरा सकता है।

पीएम मोदी को टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दी बधाई

नईदिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद और जाने-माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने मोदी को अपना दोस्त और मार्गदर्शक बताया और उनके लंबे, स्वस्थ और खुशहाल

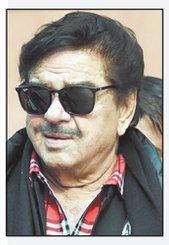

जीवन की कामना की। एक्स पर एक पोस्ट में, सिन्हा ने प्रधानमंत्री को इस उपलब्धि तक पहुँचने पर बधाई दी और इसे देश के इतिहास में सबसे लंबे कार्यकालों में से एक बताया। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्स पर लिखा कि एक सच्चे खिलाड़ी की भावना के साथ, हम समाज और देश के मार्गदर्शक और अपने मित्र, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बधाई देते हैं। यह शायद अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। हम आपके लंबे, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। जय हिंद! टीएमसी नेता का यह संदेश तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हुए।

कलकत्ता हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को आंशिक राहत

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी को हस्ताक्षर जालसाजी मामले में बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर या दंडात्मक कार्रवाई

पर रोक लगा दी है। यह मामला कथित हस्ताक्षर जालसाजी से जुड़ा है, जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आया था। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई तक जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इस सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि आरोप निराधार हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। वहीं, मामले से जुड़े पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने का फैसला किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन अगली सुनवाई तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।

ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगी वीणा विजयन

कोच्चि। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन की बेटी वीना टी ने सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में ईडी से अपनी पूछताछ स्थगित करने का अनुरोध किया है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से हैं। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीना को शुक्रवार को कोच्चि स्थित

अपने कार्यालय में जांच दल के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया था। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, वीना ने हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अपनी पेशी स्थगित करने के लिए आपातकालीन विभाग को एक ईमेल भेजा था। उन्होंने एजेंसी को यह भी सूचित किया है कि सभी आवश्यक दस्तावेज जल्द ही उनके वकील के माध्यम से जमा कर दिए जाएंगे। ईडी सूत्रों ने बताया कि एजेंसी उनकी पेशी के लिए नई तारीख के साथ एक नया समन जारी करने पर विचार करेगी। पिछले महीने, ईडी ने इस मामले से जुड़े 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें वीना और उनके पति, पूर्व मंत्री पीए मोहम्मद रियास से जुड़े परिसर भी शामिल हैं।

नटराजन नामांकन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

भोपाल/नई दिल्ली। देशभर में चर्चा का विषय बने मीनाक्षी नटराजन नामांकन रद्द मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। गुरुवार तड़के कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, सुबह सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को शुक्रवार को सुनने पर सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन

की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने अपने राज्यसभा नामांकन पत्रों को खारिज किए जाने को चुनौती दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए इसे अत्यंत तत्काल सुनवाई योग्य मामला बताया और शीघ्र सुनवाई या अंतरिम आदेश की मांग की। अदालत ने उनकी दलीलों पर संज्ञान लेते हुए मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सिंघवी ने दलील दी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने यह कहते हुए नामांकन खारिज किया कि नटराजन ने लंबित आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी।जबकि वास्तव में केवल समन जारी हुआ था और मामले में अभी तक संज्ञान भी नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा कि यहां तक कि संज्ञान भी नहीं लिया गया था, फिर भी नामांकन खारिज कर दिया गया।

ब्रिक्स में भारत की अध्यक्षता से कृषि व्यापार को मिलेगी नई दिशा

एम.एल. जाट एवं स्मिता सिरोही

भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय कर रहा है जब कृषि व्यापार की चर्चा केवल शुल्क और बाजार पहुंच तक सीमित नहीं रह गई है। जलवायु संकट, खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव, उर्वरकों की आपूर्ति में रुकावट, सतत उत्पादन से जुड़े मानक, उत्पाद के स्रोत और गुणवत्ता की डिजिटल जानकारी तथा संकट के समय बाजारों को खुला रखने की जरूरत अब कृषि व्यापार के अहम मुद्दे बन चुके हैं।

कृषि महत्वपूर्ण : ब्रिक्स के विस्तार के बाद यह समूह अब दुनिया की लगभग आधी आबादी, वैश्विक जीडीपी के करीब 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एवं विकास संस्था, अंकटाड, के हालिया आकलन के अनुसार, ब्रिक्स देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 2003 के बाद तेरह गुना से अधिक बढ़ा है और 2024 में 1.17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। कृषि इस बड़े व्यापारिक परिदृश्य का केवल एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से यह सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में है। जब खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं, उर्वरकों की आपूर्ति रुकती है या समुद्री मार्गों में अनिश्चितता आती है, तो इसका सीधा असर किसानों, उपभोक्ताओं और सरकारों पर पड़ता है। इसलिए कृषि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। ब्रिक्स देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में कई तरह की पूरकताएं हैं। ब्राजील सोयाबीन, मांस और चीनी का बड़ा निर्यातक है। रूस अनाज और उर्वरकों में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। भारत चावल, समुद्री उत्पाद, मसाले, भैंस के मांस और छोटे किसानों से जुड़ी कई कृषि वस्तुओं में मजबूत स्थिति रखता है। चीन खाद्य पदार्थों का बड़ा आयातक और प्रसंस्करण करने वाला देश है। दक्षिण अफ्रीका इस समूह को अफ्रीका के महत्वपूर्ण कृषि-खाद्य बाजारों से जोड़ता है। नए सदस्य भी इसमें नए आयाम जोड़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब लॉजिस्टिक्स, वित्त और खाद्य सुरक्षा निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। मिस्र और इथियोपिया अफ्रीका की खाद्य प्रणाली से जुड़ी चिंताओं को सामने लाते हैं, जबकि इंडोनेशिया पाम ऑयल, मत्स्य क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय कृषि की ताकत जोड़ता है। आपसी ताकतों को ठोस व्यवस्था में बदलना लेकिन केवल बड़े पैमाने और आपसी ताकतों के मेल से अपने-आप मजबूत व्यापार व्यवस्था नहीं बनती। आगामी ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भारत को यह अवसर देती है कि वह सहयोग को कुछ ठोस दिशाओं में आगे बढ़ाए। इनमें भरोसेमंद व्यापार व्यवस्था, बीज, उर्वरक और अन्य उत्पादन सामग्री की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, बेहतर बाजार जानकारी और ऐसी मूल्य श्रृंखलाएं शामिल हैं जिनमें छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो। भरोसेमंद व्यापार व्यवस्था को शुरुआती प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कृषि व्यापार में केवल माल भेजना पर्याप्त नहीं है; यह भी उतना ही जरूरी है कि उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्रोत पर भरोसा हो। कृषि व्यापार सुविधा पर 2024 के ब्रिक्स सिद्धांत पहले ही खाद्य सुरक्षा, पशु-पौध स्वास्थ्य और तकनीकी मानकों से जुड़े सहयोग, एक-दूसरे के मानकों को स्वीकार करने की व्यवस्था, कम व्यापार लागत और डिजिटल व्यापार सुविधा जैसे बुनियादी मुद्दों को मान्यता देते हैं। भारत इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल प्रमाणपत्रों, उत्पाद के स्रोत और गुणवत्ता की भरोसेमंद डिजिटल जानकारी, नियामकों के बीच तेज संवाद और उत्पादकों व निर्यातकों की क्षमता निर्माण पर जोर दे सकता है।

दूसरी प्राथमिकता मजबूत आपूर्ति श्रृंखला होनी चाहिए। खाद्य व्यापार को उर्वरक, ऊर्जा, पशु आहार, बीज, ढुलाई-भंडारण और वित्त से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भारत के लिए यह कोई दूर की चिंता नहीं है। उसके उर्वरक और ऊर्जा आयात का आधे से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आता है। इसलिए उत्पादन सामग्री की सुरक्षा सीधे कृषि की मजबूती से जुड़ी हुई है। पश्चिम एशिया के हालिया संकटों ने दिखाया है कि खाद्य पदार्थों के बाजार तक पहुंचने से बहुत पहले ही उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसलिए ब्रिक्स सहयोग में उर्वरकों और अन्य उत्पादन सामग्री के बाजारों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, भंडार और कीमतों पर पारदर्शी जानकारी, और जरूरी कृषि सामग्री की आपूर्ति में अचानक आने वाली रुकावटों को कम करने की व्यवस्था शामिल होनी चाहिए।

तीसरी प्राथमिकता बेहतर बाजार जानकारी है। ब्रिक्स अनाज विनिमय का विचार इस बात की जरूरत को दिखाता है कि खाद्य बाजारों में अधिक पारदर्शिता, बेहतर मूल्य संकेत और खाद्य सुरक्षा की तैयारी होनी चाहिए। भारत इस दिशा में ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के भीतर कृषि बाजार जानकारी से जुड़ी एक व्यवस्था का प्रस्ताव रख सकता है। यह मंच पहले से ही ज्ञान से कार्य की दिशा में विकसित किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था खाद्य भंडार, फसल की स्थिति, उर्वरक कीमतों, जहाजरानी जोखिमों, खाद्य सुरक्षा और पशु-पौध स्वास्थ्य से जुड़े अलर्ट तथा प्रमुख कृषि जिंसों के रुझानों पर नियमित जानकारी दे सकती है।

परिवहन विभाग से जुड़ी जनसमस्याओं को लेकर प्रदर्शन

कांग्रेस ने आरटीओ दफ्तर का घेराव किया व उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

दुर्ग। दुर्ग में परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरटीओ कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया।

ई-चालान में कथित गड़बड़ियों, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में देरी, वाहन मालिक नामांतरण (ट्रांसफर) की लंबी प्रक्रिया और बढ़ी हुई फीस जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आरटीओ कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता करीब आधे घंटे तक कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे और आरटीओ अधिकारी का इंतजार करते हुए जमकर नारेबाजी की।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने परिवहन विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। बाकलीवाल ने कहा कि लंबे समय से आम लोगों की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आरटीओ अधिकारी से मिलने पहुंचा।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई वाहन चालकों के एक ही मामले में दो-दो बार चालान काटे जा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के ई-चालान तीन-तीन बार जारी होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। उन्होंने इसे विभागीय खामी बताते हुए तत्काल सुधार की मांग की।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई वाहन चालकों के एक ही मामले में दो-दो बार चालान काटे जा रहे हैं। कुछ लोगों के इलेक्ट्रॉनिक चालान तीन-तीन बार जारी होने की शिकायतें भी मिली हैं। इसे विभागीय खामी बताते हुए तत्काल सुधार की मांग की गई।

पहले घोषित सहायता केंद्र भी अब तक शुरू नहीं हुई है। ऑनलाइन वाहन चलाने के लाइसेंस और वाहन नामांतरण शुल्क बढ़ने पर भी नाराजगी जताई गई। कांग्रेस ने 10 दिनों के भीतर समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर आरटीओ अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए 10 दिनों के भीतर समाधान की चेतावनी दी।

बाकलीवाल ने कहा कि यदि निर्धारित समय में समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं आरटीओ अधिकारी मृत्युंजय प्रसाद पटेल ने कहा कि ई-चालान से जुड़ी शिकायतों की जानकारी मुख्यालय को भेजी गई है।आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आरटीओ अधिकारी ने वाहन चालकों से अपील की कि वे सभी जरूरी दस्तावेज और हेलमेट के साथ ही वाहन चलाएं, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने पर कैमरों के माध्यम से ई-चालान स्वतः जारी होगा।

खेत के बीच से नहर बनाने पर किसान ने खाया जहर

रायगढ़। केलो परियोजना के तहत खेत के बीच से नहर बनाने से नाराज एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पूरा मामला रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम लिंजीर का है। जानकारी के अनुसार, ग्राम लिंजीर निवासी रविशंकर गुप्ता अपनी कृषि भूमि के बीच से प्रस्तावित नहर निर्माण का विरोध कर रहे थे। गुरुवार को प्रशासनिक अमला और पुलिस बल नहर निर्माण कार्य के लिए मौके पर पहुंचा था। महिला तहसीलदार की मौजूदगी में निर्माण कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी, जिसका किसान ने विरोध किया।

परिजनों के मुताबिक, रविशंकर गुप्ता का कहना था कि नहर को उनकी खेती योग्य जमीन के बजाय पास स्थित शासकीय भूमि से निकाला जाए। उनका आरोप है कि केलो परियोजना के लिए पहले ही उनकी 7 से 8 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है, जिसके कारण वे और जमीन देने को तैयार नहीं थे। इसी बीच प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रुकने से आक्रोशित किसान ने जहर खा लिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गंभीर अवस्था में किसान को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है।

किसान के परिजनों ने तहसीलदार और पुलिस पर दबाव बनाकर जमीन खाली कराने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन की ओर से मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि किसानों की सहमति और समस्याओं का समाधान किए बिना इस तरह की कार्रवाई से विवाद बढ़ सकता है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटा है।

भौता गांव को मिलेगी पक्की सड़क स्वास्थ्य मंत्री ने किया भूमिपूजन

एमसीबी। मनेंद्रगढ़ जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भौता के ग्रामीणों के लिए लंबे इंतजार के बाद विकास की नई उम्मीद जगी है।साल 1994 से सड़क निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों का सपना अब साकार होने जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भौता क्षेत्र में पक्की डामरीकृत सड़क का निर्माण शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने सड़क निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत की। लगभग 13।5 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण करीब 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। सड़क बनने के बाद भौता सहित आसपास के कई गांवों के लोगों को वर्षों पुरानी आवागमन की समस्या से राहत मिलेगी। भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इसमें एक सड़क नारायणपुर क्षेत्र में, दूसरी भौता पंचायत अंतर्गत भौता खुखिया मार्ग से बड़ाभौता तक बनाई जाएगी।इस मार्ग का करीब साढ़े आठ किलोमीटर हिस्सा लंबे समय से खराब स्थिति में था।बारिश के दिनों में यहां बाइक से भी आवागमन करना मुश्किल हो जाता था। ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के कार्यों के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, वहीं विद्यार्थियों और मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

श्रमिक पिता ने लिखा गीत, बेटी ने गाकर जीता दिल

एसपी ने किया सम्मानित

धमतरी। पुलिस और जनता के बीच विश्वास की अनूठी मिसाल उस समय देखने को मिली, जब नवागांव कंडेल निवासी श्रमिक और गीतकार रविशंकर पटेल अपनी बेटी हर्षलता पटेल के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। पिता के लिखे गीत को बेटी ने गाया और सभी का दिल जीत लिया। रविशंकर पटेल पेशे से मजदूर हैं। उन्होंने धमतरी पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा तस्करी, जुआ-सट्टा और चाकूबाजी जैसे अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से प्रभावित होकर पुलिस की जनसेवा, कर्तव्यनिष्ठा और समाज के प्रति समर्पण पर आधारित गीत की रचना की है। उनकी बेटी हर्षलता, एक छात्रा और उभरती हुई गायिका हैं। बेटी ने इस गीत को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गाया। गीत में पुलिस की सेवा भावना, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में निभाई जा रही भूमिका और आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रति समर्पण का वर्णन किया गया है। हर्षलता की प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली रही कि वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी भावुक हो उठे और हर्षलता की प्रतिभा की सराहना की। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने पिता-पुत्री की इस अनूठी जोड़ी के प्रयास की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कला और साहित्य समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम हैं। पुलिस के प्रति सम्मान और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाली ऐसी रचनात्मक पहल समाज और पुलिस के बीच सकारात्मक संवाद को मजबूत बनाती है। एसपी ने हर्षलता के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर प्रगति और सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हर्षलता की गायन प्रतिभा की प्रशंसा की। यह अवसर केवल एक सम्मान समारोह नहीं था।

21 साल बाद फरार हत्यारा गिरफ्तार

जगदलपुर। केंद्रीय जेल से वर्ष 2005 में पैरोल पर छूटा एक हत्या का आरोपी 21 साल बाद गिरफ्तार हुआ है। वह पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद वापस नहीं लौटा था।

पुलिस ने उसे तेलंगाना राज्य से पकड़ा है। आरोपी सोढ़ी मासा 45 वर्ष का है और ग्राम गाटम डोंगरीपारा का निवासी है। उसे थाना कटेकल्याण, जिला दंतेवाड़ा के हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सोढ़ी मासा वर्ष 2001 से केंद्रीय कारागृह जगदलपुर में निरुद्ध था।

वर्ष 2005 में उसे 14 दिनों की पैरोल पर अपने गृह ग्राम जाने की अनुमति मिली थी। लेकिन पैरोल अवधि खत्म होने पर वह जेल वापस नहीं लौटा और फरार हो गया। फरारी के दौरान उसने तेलंगाना के कोत्तागुडेम के कासनपल्ली क्षेत्र में अपना नाम बदल लिया था। वह वहां लालाराम सोढ़ी के नाम से छिपकर रह रहा था। थाना कटेकल्याण पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी का पुत्र हड़मा उर्फ सुरेश सोढ़ी गांव आया हुआ है। पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने अपने पिता सोढ़ी मासा के तेलंगाना में नाम बदलकर रहने की जानकारी दी।

इस सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम को तत्काल तेलंगाना भेजा गया। पुलिस टीम ने कोत्तागुडेम, तेलंगाना से फरार आरोपी सोढ़ी मासा को गिरफ्तार किया।

हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार, कहा: प्राइवेट रिकवरी एजेंट नहीं बन सकती पुलिस

बिलासपुर। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। एक मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है कि पुलिस निजी वसूली एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 बीनएसएस के नियमों का उल्लंघन कर एक फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी के बैंक खाते के करोड़ों रुपए 'होल्ड' करने के पुलिस के आदेश को खारिज कर दिया है। दरअसल, नई दिल्ली की 'ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एनबीएफसी कंपनी उद्योगों और छोटे व्यवसायियों को लोन देने का काम करती है। कंपनी का एक खाता कोटक महिंद्रा बैंक रायपुर ब्रांच में संचालित है, जिसमें देशभर के कर्जदारों की ईएमआई के तौर पर प्रतिदिन 12 से 15 करोड़ रुपए आते हैं। कंपनी ने रायपुर की एक फर्म श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड को कच्चा माल खरीदने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की लोन सुविधा दी। बाद में श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट्स का माल सप्लाई करने वाली एक अन्य कंपनी ओएफबी टेक से वजन में धोखाधड़ी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद मंदिर हसौद थाना में करीब 6.9 लाख रुपए (जो बाद में 43.38 लाख रुपये आंकी गई) की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। मामले की जांच करते हुए मंदिर हसौद पुलिस ने बिना किसी ठोस कानूनी आधार के आक्सीजो फाइनेंस कंपनी के खाते से लेनदेन पर पूरी तरह रोक लगा दी और बाद में कंपनी के 53,47,17,835 रुपए (53.47 करोड़ रुपए) की राशि को 'होल्ड' कर दिया। बाद में जब मामला बढ़ा तो पुलिस ने इसे घटाकर 43.38 लाख रुपए होल्ड रखने का नया आदेश जारी किया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

झारखंड से छत्तीसगढ़ में नशीले इंजेक्शन खपाने वाले जेल दाखिल

जशपुर। जशपुर पुलिस ने झारखंड से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर खपाने ले जाए जा रहे भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने तस्करी गिरोह से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीन आरोपी हाथीसार के जंगल से पकड़े गए, एक फरार आरोपी को अंबिकापुर से गिरफ्तार किया, जबकि नशीले इंजेक्शन उपलब्ध कराने वाले मुख्य सप्लायर को झारखंड के गुमला जिले से दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 12,850 एमएल नशीले इंजेक्शन, एक कार, एक मोटरसाइकिल, चार मोबाइल फोन और नकदी सहित लगभग 3।98 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने बताया कि रात सिटी कोतवाली जशपुर की टीम सारूडीह मार्ग पर नियमित गश्त और पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध कार पुलिस को देखकर तेजी से जंगल की ओर भागने लगी। वाहन की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसका पीछा किया। पीछा किए जाने पर कार सवार आरोपी वाहन को जंगल किनारे छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए।

ट्रक, कोयला और पैसे लेकर फरार ड्राइवर गिरफ्तार

सूरजपुर। ट्रांसपोर्टर और कोयला व्यवसायी के साथ विश्वासघात और अमानत में खयानत का मामला सामने आया है। मामला दिसंबर 2024 का है। एक ड्राइवर ट्रक, कोयला और ट्रक में डीजल डलवाने के लिए दिए रुपये लेकर फरार हो गया था। मामले में सूरजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को पंजाब से गिरफ्तार किया है। जबकि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल अन्य मुख्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया, मामला कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रेहर कोयला खदान का है। खदान से जुड़े एक लिफ्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि दो ट्रक चालकों को कोयला परिवहन के लिए लगाया गया था। खदान से कोयला लोडकर उन्हें ओडिशा जाने के लिए भेजा गया था। डीजल खर्च के लिए दोनों ड्राइवर को 30-30 हजार रुपये भी दिए गए थे। लेकिन ट्रक चालकों ने ट्रांसपोर्टर के साथ विश्वासघात किया। एसडीओपी ने बताया कि जसपाल सिंह अपने एक साथी के साथ रेहर कोयला खदान पहुंचा।

कोरबा में 15 अक्टूबर तक रेत निकालने पर लगी रोक

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर खनिज विभाग ने एक बड़ा अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य नदियों का संरक्षण और अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। जिले के सभी रेत घाटों से रेत निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। यह प्रतिबंध 10 जून से 15 अक्टूबर तक मानसून अवधि के लिए है। उप संचालक खनि प्रशासन के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबंध सुनिश्चित कराने के लिए दो खनिज उड़नदस्ता दलों ने बुधवार को जिले भर में औचक निरीक्षण किया। टीमों ने जोगीपाली, तरदा, कुदुरमाल सहित कई वैध रेत घाटों का जायजा लिया। उन्होंने घाट संचालकों और श्रमिकों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्हें बताया गया कि इस अवधि में रेत का उत्खनन और परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। टीम ने मौके पर ही घाटों का जायजा लिया। इससे प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराया गया। निरीक्षण के दौरान कुदमुरा रेत घाट में प्रतिबंध के बावजूद उत्खनन पाया गया। खनिज विभाग ने तत्काल चेन माउंटेन मशीन जब्त कर सील कर दी।

चोरी के 40 तोला सोने के आभूषण चांदी बरामद

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिले में बीते दिनों अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है। जीपीएम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए लाखों रुपये मूल्य के सोने चांदी के आभूषण, वाहन, मोबाइल फोन और चोरी में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार पिछले कुछ महीनों से चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं। इन मामलों में अपराध दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश की जा रही थी। जांच के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें चोरी की कई वारदातों का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में कुल सात चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। इनमें कोटमी थाना क्षेत्र की तीन, मरवाही थाना क्षेत्र की दो और मध्यप्रदेश के जैतहरी थाना क्षेत्र की एक चोरी की वारदात शामिल है।

सड़क निर्माण में देरी पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

जगदलपुर। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के एक प्रमुख मार्ग पर अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य के विरोध में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में हुआ। कांग्रेस ने सड़क की बदहाल स्थिति के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सुशील मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। शहर की यह मुख्य सड़क महीनों से अधूरी पड़ी है। इससे प्रतिदिन हजारों नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसी मार्ग से भाजपा के बड़े नेताओं का नियमित आवागमन होता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक का शासकीय कार्यालय भी इसी मार्ग पर स्थित है। इस वार्ड के पार्षद भी भारतीय जनता पाटी से हैं, फिर भी सड़क की दुर्दशा पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है।

दुर्ग के धान खरीदी केंद्रों में ढाई करोड़ का धान शॉर्टेज

प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

दुर्ग। दुर्ग जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी केंद्रों में बड़े पैमाने पर धान की कमी सामने आने से हड़कंप मच गया है। जिले के धान उपार्जन केंद्रों के भौतिक सत्यापन में हजारों क्विंटल धान रिकॉर्ड से कम मिला है। मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने संबंधित समितियों और केंद्र प्रभारियों को नोटिस जारी कर चार दिन के भीतर धान अथवा उसकी कीमत जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

दरअसल जांच में जिले के 61 से अधिक धान उपार्जन केंद्रों में कुल 27 हजार 900 क्विंटल से ज्यादा धान की कमी पाई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब ढाई करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले धमधा और जामगांव आर समिति के प्रभारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। धमधा समिति प्रभारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि जामगांव आर समिति प्रभारी की अग्रिम राहत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

वहीं ननकट्टी समिति ने कमी की राशि जमा कर दी है।वहीं जिला सहकारिता बैंक अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि किसी ने जानबूझकर धान शॉर्टेज किया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

जांच रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 4 हजार 646 क्विंटल धान की कमी धमधा समिति में मिली है। इसके अलावा करेली, बरहापुर, डीडाभाठा और केसरा समितियों में भी बड़ी मात्रा में धान कम पाया गया। अधिकारियों का कहना है कि खरीदी प्रक्रिया में नहीं बल्कि धान के उठाव, परिवहन, भंडारण और रिकॉर्ड मिलान में गड़बड़ियां सामने आई हैं।

सक्ती में प्रधान मंत्री आवास में फर्जीवाड़ा का आरोप

बाराद्वार नगर पंचायत नेता प्रतिपक्ष ने सौंपे सबूत, सीएमओ ने बनाई जांच टीम

सक्ती। पीएम आवास को लेकर बाराद्वार नगर पंचायत के अधिकारी और जनप्रतिधि सवालों में घिरते नजर आ रहे हैं।गरीबों को आवास देने के नाम पर बड़े पैमाने में शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में कूट रचना की शिकायत अब सही साबित होते दिख रही है। वहीं नगर पंचायत बाराद्वार के अध्यक्ष नारायण कुर्रे के मीडिया को दिए बयान ने मामले को फिर से गरमा दिया है। नगर पंचायत बाराद्वार के अध्यक्ष नारायण कुर्रे के बयान ने मामले को फिर से गरमा दिया है।अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस सरकार में भी वहां कब्जा कर आवास बनाए गए थे, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही। घास भूमि में इतने सारे मकान कैसे बन गए जो 10 वर्षों से वहां रह रहे हैं इस पर भी जांच होनी चाहिए।कांग्रेस कार्यकाल में बड़े पैमाने पर आबादी भूमि की खरीदी बिक्री हुई है इस पर जांच क्यों नहीं हो रही- नारायण कुर्रे, अध्यक्ष नगर पंचायत बाराद्वारबाराद्वार नगर पंचायत में 288 पीएम आवास स्वीकृति के लिए दस्तावेज तैयार किए गए हैं। इसमें करीब 246 आवास आबादी ओर घास मद की भूमि में बनाए जा रहे जबकि घास मद की भूमि का उपयोग आवास बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन नगर पंचायत के जिम्मेदारों ने पटवारी के साथ सांठगांठ कर घास भूमि को आबादी भूमि बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए।साथ ही आवास स्वीकृति के लिए शासन को भी भेज दिया था। इसकी शिकायत नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष अभिषेक राय ने अधिकारियों से की है।

शिकायत के बाद मामले में जांच टीम गठित कर दी गई है जो इस मामले के संबंधित दस्तावेज ओर साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके द्वारा इस फर्जीवाड़ा को लेकर सारे साक्ष्य ओर जमीन के दस्तावेज जांच अधिकारी को सौंप दिया है। अब जांच अधिकारी इस पर क्या कार्यवाही करते है यह देखना होगा।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका से लेखिका श्रीमती अग्रवाल ने की मुलाकात

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से गुरुवार को लोक भवन में लेखिका श्रीमती पूजा अग्रवाल ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने अपनी स्वरचित कहानी संग्रह 'माटी के पंख' की प्रति राज्यपाल को भेंट की। लेखिका ने राज्यपाल को पुस्तक की विषय-वस्तु से अवगत कराते हुए बताया कि यह कहानी संग्रह प्रकृति संरक्षण का संदेश देती है। पुस्तक में मानवीय संवेदनाओं और प्रकृति के बीच के गहरे संबंधों को विभिन्न कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। राज्यपाल ने पुस्तक के विषय और उसके संदेश की सराहना करते हुए कहा कि प्रकृति के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने लेखिका पूजा अग्रवाल को उनके रचनात्मक प्रयास के लिए शुभकामनाएं दीं तथा पुस्तक के व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचने की कामना की।

मंत्री राजवाड़े की पहल से बृजेश्वर सागर जलाशय के नवीनीकरण राशि स्वीकृत

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के सतत प्रयासों से सूरजपुर जिले के विकासखंड भैयाथान स्थित बृजेश्वर सागर जलाशय योजना के नवीनीकरण कार्य के लिए 4 करोड़ 94 लाख 13 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा तथा किसानों को बेहतर कृषि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत इस कार्य के पूर्ण होने पर 464 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। इससे किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तथा क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सिंचाई संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। बृजेश्वर सागर जलाशय के नवीनीकरण से भैयाथान क्षेत्र के किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा और खेती अधिक लाभकारी बन सकेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। यह परियोजना क्षेत्र में जल संरक्षण एवं कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

कोनी-मोपका बायपास के लिए निविदा को मंजूरी

रायपुर। राज्य शासन ने बिलासपुर में कोनी (सेंदरी)-मोपका बायपास सड़क के लिए 75 करोड़ 73 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दे दी है। इस राशि से 13.40 किलोमीटर फोरलेन सीमेंट क्रांकीट सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर संभाग क्रमांक-1 के कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप सड़क का निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग ने कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित कार्य का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य किसी अन्य को सब-लेट नहीं किया जाएगा तथा कार्य संपादन के लिए पावर-ऑफ-अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। राज्य शासन ने अनुबंध से पहले ठेकेदार से एपीएस (Additional Performance Security) की राशि का एफडीआर (Fixed Deposit Receipt) प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।

एमजी रोड स्थित जया ऑटोमोबाइल में लगी भीषण आग

रायपुर। राजधानी रायपुर के एमजी रोड स्थित जया ऑटोमोबाइल की बिल्डिंग में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। सुबह 10 बजे से लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका है। लेकिन अभी भी आग की तपिश बने होने से पानी डाला जा रहा है। आग बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंजिल तक पहुंच चुकी थी इसलिए आजू बाजू के दुकानों को भी तत्काल में बंद करवाया गया वहीं दोनों छोर से रास्ते बेरिकेड्स लगाकर बंद किए गए। मौदहापारा थाना पुलिस,निगम प्रशासन,अग्निशमन दल व रहवासियों ने खुद मोर्चा संभाल रखा था। घटना मौदहापारा थाना क्षेत्र की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह दुकान खुलने के कुछ ही समय बाद अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया था। देखते ही देखते आग फैलते चली गई। बताया जा रहा एमसीबी उठाने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ था। शोरूम के अंदर बड़ी मात्रा में गाडियों के स्पेयर पार्ट्स, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक का सामान और लुब्रिकेंट्स (ज्वलनशील तेल) रखे हुए थे, जिससे आग फैली है। आग पर काबू पाने अब तक फायर ब्रिगेड की 6 गाडियों की मदद ली गई है। जेसीबी से दीवार तोड़कर टीम अंदर घुसी तब कहीं पानी असर करना शुरु किया। वैसे तो पूरा समान जल चुका है पर कितने का नुकसान हुआ है इसका आकलन बाद में पता चल पायेगा।

पीएम धन-धान्य कृषि योजना में जशपुर मॉडल बना राष्ट्रीय पहचान का केंद्र

केंद्र सरकार ने कृषि नवाचार, जल संरक्षण और किसान आय वृद्धि के प्रयासों की सराहना की

रायपुर। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कृषि विकास, जल संरक्षण एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए जशपुर जिले में किए जा रहे नवाचारों को भारत सरकार ने सराहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव तथा योजना के केंद्रीय नोडल अधिकारी श्री पी. अंबलगन (आईएएस) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले की समीक्षा करते हुए जशपुर मॉडल को प्रभावी, दूरदर्शी और किसान हितैषी बताया।

समीक्षा बैठक में वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों तथा वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना में सुगंधित एवं औषधीय फसलों के क्लस्टर विकास, संविदा खेती को प्रोत्साहन, जीराफूल धान के रकबे का विस्तार, निर्यात योग्य धान क्लस्टर, सामुदायिक बीज बैंक, ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर तथा कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और विपणन व्यवस्था को प्रमुखता दी गई है। बैठक में खरीफ सीजन 2026-27 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि किसानों के लिए बीज एवं उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। संभावित एल-नीनो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अल्प अवधि वाली धान किस्मों के साथ मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि मौसमीय चुनौतियों के बावजूद उत्पादन प्रभावित न हो।

जल संचय जनभागीदारी अभियान के तहत जिले में संचालित जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन कार्यों की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से जल संसाधनों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। संयुक्त सचिव श्री अंबलगन ने इन प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जल संरक्षण कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का आधार है। उन्होंने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता एवं ग्रामीण विकास विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सशक्तिकरण, मूल्य संवर्धन एवं बाजार संपर्क गतिविधियों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। अंबलगन ने कहा कि किसानों की आय में स्थायी वृद्धि के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ कृषि आधारित उद्यमिता, आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण और विपणन को भी समान महत्व देना आवश्यक है। उन्होंने जिले में चल रहे नवाचारों की सराहना करते हुए कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जशपुर में किसानों की आय वृद्धि, कृषि विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण एवं कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयास अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। इससे किसानों को आधुनिक तकनीकों का लाभ मिलने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद है।

पीएम मोदी के सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज ने दी बधाई

■ भारत की निरंतर प्रगति के लिए की अरदास

रायपुर। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति, समृद्धि और विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ता रहे इसके लिए अरदास भी की।

छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान स्थापित की है। उनके कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और जनकल्याणकारी नीतियों के परिणामस्वरूप देश विकास, आत्मनिर्भरता, अधोसंरचना, डिजिटल क्रांति तथा वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के अटूट विश्वास, उनके समर्पित कार्यों एवं राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। देश के करोड़ों नागरिकों का विश्वास और समर्थन उन्हें निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज ने बधाई दी- भारत की निरंतर प्रगति के लिए की अरदास की

छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा, समाज के अन्य प्रमुख सदस्यों नरेंद्र सिंह हरगोत्रा, स्वर्ण सिंह चावला, कुलवंत सिंह खालसा, मनजीत सिंह भाटिया, देवेंद्र सिंह चावला, रणजीत सिंह खनूजा, अमृत सिंह सूर, जसप्रीत सिंह चावला, इंदर पाल सिंह गांधी, गुरमीत सिंह छाबड़ा, मानवेंद्र सिंह डडियाला, सवर्ण सिंह अजमानी,अत्तर सिंह, जागीर सिंह बावा ने कामना की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति, समृद्धि और विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ता रहे तथा देशवासियों को विकास एवं सुशासन का लाभ मिलता रहे।

रामानुजगंज अस्पताल को मिली 1.66 करोड़ की स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात

रायपुर। आदिम जाति एवं कृषि विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम के विशेष प्रयासों से जिला बलरामपुर के नगर पंचायत रामानुजगंज (विकासखंड रामचंद्रपुर) स्थित 100 बिस्तर शासकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 65 लाख 82 हजार 500 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति से अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

स्वीकृत राशि से अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर (ओटी) सेटअप, डायलिसिस यूनिट तथा ब्लड स्टोरेज यूनिट को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। ओटी सेटअप के लिए वेंटिलेटर मशीन, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, ओटी लाइट, ओटी टेबल, मल्टीपैरा मॉनिटर, ट्रूनैट मशीन, सीबीसी मशीन, माइक्रोस्कोप, कॉटरी मशीन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एवं अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी प्रकार डायलिसिस यूनिट की स्थापना के लिए दो डायलिसिस यूनिट, मल्टीपैरा मॉनिटर, 100 एलपीएच क्षमता का आरओ प्लांट, एयर कंडीशनर तथा अन्य आवश्यक उपकरणों हेतु 36.10 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा ब्लड स्टोरेज यूनिट के लिए माइक्रोस्कोप, डीप फ्रीजर, ब्लड स्टोरेज रेफ्रिजरेटर, सेंट्रीफ्यूज मशीन एवं अन्य उपकरणों की स्थापना हेतु 6.30 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना के बाद अस्पताल में ऑपरेशन, डायलिसिस, रक्त भंडारण, आपातकालीन उपचार तथा गंभीर मरीजों की चिकित्सा सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे मरीजों को उपचार के लिए अंबिकापुर, रायपुर अथवा अन्य बड़े शहरों का रुख करने की आवश्यकता कम पड़ेगी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी।

श्रीलंका श्रृंखला के लिए टी-20 और वनडे में मिली महक नरवासे को जगह

वित्त मंत्री ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ की प्रतिभावान युवा क्रिकेटर महक नरवासे का श्रीलंका श्रृंखला के लिए भारत की महिला अंडर-19 टी-20 एवं वनडे दोनों टीमों में चयन हुआ है। उप कप्तान के रूप में चयनित महक की इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी और गर्व का माहौल है।

महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि महक की यह उपलब्धि उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन, प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टीम में चयनित होकर महक ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है।

चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं और खेल जगत में भी नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। महक नरवासे का भारतीय टीम में चयन प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि महक की सफलता प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ियों, विशेषकर बेटियों को विभिन्न खेलों में आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेगी। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि महक श्रीलंका दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देंगी तथा भविष्य में देश और छत्तीसगढ़ का गौरव और अधिक बढ़ाएंगी।

खुशियों की चाबी से साकार हो रहा पक्के घर का सपना

रायपुर। अपना पक्का घर हर परिवार का सपना होता है। बालोद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इस सपने को तेजी से साकार कर रही है। सुशासन तिहार 2026 के दौरान बालोद जिले में आयोजित समाधान शिविरों में जब जनप्रतिनिधियों ने आवास लाभार्थियों को उनके नए घरों की 'खुशियों की चाबी' सौंपी, तो अनेक परिवारों की वर्षों पुरानी आकांक्षा पूरी होने की खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक उठी।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत 54,151 आवासों में से 48,421 आवास पूर्ण हो चुके हैं। यह कुल लक्ष्य का 89.42 प्रतिशत है। शेष 5,730 आवास निर्माणाधीन हैं, जिन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के लिए लाभार्थियों से लगातार संपर्क कर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सुशासन तिहार के शिविरों में प्रत्येक शिविर में औसतन 5 से 7 आवास हितग्राहियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। लाभार्थियों ने मंच से अपने अनुभव साझा करते हुए अन्य ग्रामीणों से समय पर आवास निर्माण पूरा करने तथा जल संरक्षण के लिए सोकपिट निर्माण कराने की अपील भी की।

योजना के तहत निर्माण कार्यों में वित्तीय बाधा न आए, इसके लिए शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्यों को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई है। इसी क्रम में बालोद जिले के 3,278 लाभार्थियों के लिए 10.12 करोड़ रुपये के एफटीओ (फंड ट्रांसफर ऑर्डर) जारी किए गए हैं। यह राशि शीघ्र ही डीबीटी के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंचेगी। इससे आवास निर्माण में गति आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की तस्वीर और अधिक सशक्त होगी।

आर्द्रभूमि संरक्षण में जनभागीदारी को मिलेगा बढ़ावा

रायपुर। आर्द्रभूमियां हमारी प्रकृति का सबसे उत्पादक और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन्हें अक्सर प्रकृति के गुर्दे या जैविक सुपरमार्केट कहा जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण और मानव जीवन के लिए कई अनमोल सेवाएं प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की हजारों प्रजातियों (विशेषकर प्रवासी पक्षियों, उभयचरों और मछलियों) का प्रमुख प्राकृतिक आवास हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए ये बेहद जरूरी हैं। छत्तीसगढ़ में आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के संरक्षण और सतत प्रबंधन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से रायपुर में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफईएस) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों, शोध संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों तथा समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री मथेश्वरन वी. (आईएफएस) ने किया। उन्होंने कहा कि आर्द्रभूमियां जल संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और स्थानीय आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राज्य में आर्द्रभूमियों की जियो टैगिंग, वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण और रामसर स्थलों की पहचान जैसे कार्यों में नागरिकों और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण रही है।

एफईएस की अध्ययन प्रमुख प्रतीति प्रियदर्शिनी ने जल शासन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जल को साझा प्राकृतिक संसाधन मानकर पूरे परिदृश्य स्तर पर प्रबंधन की आवश्यकता है। उन्होंने जल संरक्षण से जुड़े संस्थानों को और अधिक मजबूत एवं समन्वित बनाने पर जोर दिया।

मुख्य वक्ता एवं मनरेगा आयुक्त ने कहा कि आर्द्रभूमियों के महत्व को सरल भाषा में गांव-गांव तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समुदायों को केवल सहभागी नहीं, बल्कि संरक्षण कार्यों का भागीदार बनाना होगा। जलदूत, क्लार्ट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग से जल प्रबंधन को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

आदिम जाति कल्याण विभाग में तीन अधिकारियों का तबादला

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग ने प्रशासनिक आधार पर तीन अपर संचालकों का तबादला करते हुए नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित जनजातीय विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए यह व्यवस्था की गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष केंद्रीय सहायता योजना (बस्तर पैकेज), धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए), प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन), वन अधिकार अधिनियम-2006, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, विभागीय छात्रावास एवं आश्रम संचालन, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों तथा एकीकृत आदिवासी विकास प्राधिकरण (आईटीडीए) की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।

इन अधिकारियों का तबादला

1. जितेंद्र कुमार गुप्ता, अपर संचालक

वर्तमान पदस्थापना: कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर।

नई पदस्थापना : अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, बिलासपुर।

अतिरिक्त दायित्व : सरगुजा संभाग की विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के लिए नोडल अधिकारी।

मुख्यालय : अंबिकापुर (जिला सरगुजा)।

2. राधेश्याम भोई, अपर संचालक

वर्तमान पदस्थापना: कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर।

नई पदस्थापना: अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, जगदलपुर।

अतिरिक्त दायित्व : बस्तर संभाग की विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के लिए नोडल अधिकारी।

मुख्यालय : जगदलपुर (जिला बस्तर)।

3. तारकेश्वर देवांगन, अपर संचालक

वर्तमान पदस्थापना : अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, बिलासपुर।

नई पदस्थापना: कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

15 जून तक ज्वाइन करने के निर्देश

आदिम जाति विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों को एकपक्षीय रूप से कार्यमुक्त करते हुए 15 जून 2026 तक नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जून 2026 का वेतन नई पदस्थापना वाले कार्यालय से आहरित किया जाएगा।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

पत्र क्र. 740/व.ले.लि./2026-27 जशपुर, दिनांक 05/06/2026

पूर्व में जारी राजपुरी व्यपवर्तन योजना का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य का प्रथम निविदा आमंत्रण जी नम्बर G-262700741/6, आमंत्रित किया गया था। निविदा कार्यक्रम में लिपीकीय त्रुटि के कारण कार्य पूर्णता दिवस 18 माह की जगह 11 माह अंकित हो गया था। जिसे सुधार कर निविदा कार्यक्रम पुन: स्वीकृत करा कर निविदा आमंत्रित की जा रही है। अत: पूर्व में जारी निविदा सिस्टम क्रमांक 190801 निविदा सूचना क्रमांक 01/व.ले.लि./2026-27 दिनांक 13.05.2026 निविदा की लागत जी.एस.टी. छोड़ कर 877.82 लाख प्रथम आमंत्रण को निरस्त किया जाता है।

कार्यपालन अभियंता
जी-262701293/8 जल संसाधन संभाग जशपुर

ममता की पार्टी टीएमसी के हालात क्यों बिगड़ गए?

सौरभ वार्ष्णेय

पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी अजेय दिखाई देने वाली ममत बेनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी आज गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष, बगावत और नेतृत्व को लेकर सवाल लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर बिंदूवार मंथन करेंगे तो सर्व प्रथम सत्ता-विरोधी माहौल का असर दिखाई दे रहा है। लगभग 15 वर्षों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में रहने के बाद टीएमसी को स्वाभाविक रूप से सत्ता-विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार, स्थानीय स्तर पर कथित कट मनी संस्कृति, प्रशासनिक अक्षमता और कुछ चर्चित घोटालों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचाया। कई विश्लेषकों का मानना है कि जनता के एक वर्ग में बदलाव की इच्छा मजबूत हो गई थी। टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा ममता बनर्जी का व्यक्तिगत जनाधार रहा है। लेकिन समय के साथ पार्टी में नेतृत्व का अत्यधिक केंद्रीकरण दिखाई देने लगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बेनर्जी की भूमिका को लेकर भी संगठन के भीतर मतभेद सामने आए हैं। हाल के घटनाक्रमों में कई नेताओं और सांसदों द्वारा असंतोष व्यक्त किए जाने की खबरें आई हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बड़ी संख्या में विधायकों ने बागी रुख अपनाया। रिपोर्टों के अनुसार 58 से अधिक विधायकों ने अलग समूह का समर्थन किया और पार्टी नेतृत्व को खुली चुनौती दी। इससे टीएमसी की एकजुटता पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। चुनावी हार के बाद कई स्थानीय इकाइयों और समितियों को भंग करने की नौबत आई। यह कदम आत्ममंथन के लिए उठाया गया बताया गया, लेकिन इससे यह भी संकेत मिला कि पार्टी का संगठनात्मक ढाँचा दबाव में है। पार्टी के कुछ नेताओं पर लगे आरोप, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और हस्ताक्षर जालसाजी जैसे विवादों ने भी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। विपक्ष इन मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पार्टी को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। टीएमसी का संकट केवल चुनावी हार का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व संबंधी प्रश्नों और लंबे समय तक सत्ता में रहने से पैदा हुई चुनौतियों का संयुक्त परिणाम है। फिर भी ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की सबसे संघर्षशील नेताओं में गिनी जाती हैं। यदि वे संगठन को पुनर्गठित करने, असंतुष्ट नेताओं को साथ लाने और जनता के बीच विश्वास बहाल करने में सफल रहती हैं, तो टीएमसी फिर से मजबूत वापसी कर सकती है। लेकिन यदि आंतरिक कलह और नेतृत्व विवाद जारी रहे, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी का प्रभाव पहले जैसा बनाए रखना कठिन हो सकता है। वर्तमान संकट पार्टी के लिए आत्ममंथन का अवसर भी है और अस्तित्व की चुनौती भी। हाल के दिनों में राज्यसभा सांसद सुखेंदु सेखर रॉय के इस्तीफे और कई सांसदों के असंतोष की खबरों ने यह संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर असहमति अब खुलकर सामने आ रही है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्यों में बढ़ते बिखराव के पीछे कई कारण दिखाई देते हैं। पहला कारण नेतृत्व को लेकर असंतोष है। पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सीमित दायरे में सिमट गई है और वरिष्ठ नेताओं की राय को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद यह असंतोष और बढ़ गया है। दूसरा कारण राजनीतिक भविष्य की चिंता है। सत्ता से बाहर होने के बाद अनेक सांसद और विधायक अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं। ऐसे समय में कुछ नेताओं द्वारा नए राजनीतिक विकल्प तलाशना स्वाभाविक माना जा रहा है।

नेतृत्व वह है जो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दे

डॉ. रमन सिंह

10 जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यह केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास, आशाओं और आकांक्षाओं की विजय है। मुझे आज भी वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह उद्घोष याद है जब उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 1984 में जब भाजपा केवल दो सीटों पर सिमट गई, तब विरोधियों ने उपहास किया, लेकिन हम कार्यकर्ताओं का विश्वास अडिग था। हमें भरोसा था कि यह संघर्ष एक दिन राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन बनेगा और फिर वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 282 सीटों के ऐतिहासिक जनादेश ने उस विश्वास को साकार कर दिया।

26 मई 2014 को जब श्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब स्पष्ट हो गया था कि यह केवल सरकार का नहीं, बल्कि राष्ट्र के विचार का परिवर्तन है। यह राजनीति को सत्ता से सेवा की ओर ले जाने का संकल्प था। प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी जी द्वारा प्रारंभिक फैसलों में एक संकल्प था स्वच्छ भारत अभियान जिसे मैं मोदी जी की सबसे दूरदर्शी निर्णयों में से एक मानता हूं। भारत में कभी स्वच्छता को सिर्फ शब्दों तक सीमित बनाकर रख दिया गया था, लेकिन श्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का सन्देश देकर इसे जनआंदोलन बना दिया और 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करवाकर न सिर्फ देश को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई, बल्कि करोड़ों माताओं-बहनों की गरिमा और सम्मान की रक्षा की। 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए मुझे नरेंद्र भाई मोदी के साथ अनेक अवसरों पर काम करने और संवाद करने का अवसर मिला। मैंने उन्हें बहुत निकट से देखा है, एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद तक पहुंचे मोदी जी आज भी गांव, गरीब, किसान और वंचित वर्ग की पीड़ा को उसी संवेदनशीलता से समझते हैं। यही कारण है कि वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आशा के प्रतीक बन चुके हैं।

मुझे वह अवसर भी याद है जब छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई स्वयं उपस्थित हुए थे। उन्होंने तब भी कहा था कि गरीब का सम्मान और उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति ही सुशासन का सबसे बड़ा आधार है। आज जब श्री मोदी जी के नेतृत्व में 81 करोड़ से अधिक देशवासियों को नि:शुल्क राशन मिल रहा है, तब उनकी वही संवेदनशील सोच राष्ट्रीय नीति का रूप ले चुकी है।

पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के 60 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर प्राप्त हुए हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे पहुंची है। गरीब कल्याण के इस व्यापक दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम महिला सशक्तिकरण रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी जी भली-भांति जानते हैं कि यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसकी आधी आबादी को विकास की मुख्यधारा में सम्मानजनक भागीदारी देनी होगी। इस दिशा में तीन तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात हो या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के लिए 33त्न आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास। ये सभी निर्णय इस बात का प्रमाण हैं कि पिछले 12 वर्षों में मोदी जी ने विकास को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक न्याय, सम्मान और जनकल्याण का माध्यम बनाया है।

लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का विकास मॉडल केवल सामाजिक परिवर्तन तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जनकल्याण की योजनाओं के साथ-साथ देश की आधारभूत संरचना भी उसी गति से विकसित हो, जो विकसित भारत की मजबूत नींव बन सके। इसका स्पष्ट प्रमाण उनके 12 वर्ष के कार्यकाल में दिखाई देता है जहां उन्होंने भारत के विकास को नई गति दी है।

चिनाब रेल ब्रिज, अटल सेतु, वंदे भारत ट्रेन के साथ ही 64 लाख किलोमीटर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हुए विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बनाने की बात हो या 1155 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क जैसे अनेकों कार्य श्री मोदी जी के नेतृत्व में यह विकास कार्य आज नए भारत की पहचान बन चुके हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब नेतृत्व में स्पष्ट दृष्टि और दृढ़ इच्छाशक्ति हो। स्वाभाविक रूप से इतनी व्यापक आधारभूत संरचना का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दिया और भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करना प्रारंभ किया। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, तब भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज, मात्र एक दशक के भीतर, भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह परिवर्तन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, साहसिक आर्थिक सुधारों और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाली नीतियों का प्रतिफल है।

आज भारत लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा है और तेजी से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच भी भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। यह केवल विकास दर का विषय नहीं, बल्कि विश्व समुदाय द्वारा भारत और उसके नेतृत्व पर व्यक्त किए जा रहे बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आंकलनों के अनुसार पिछले वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह उपलब्धि करोड़ों परिवारों के जीवन में आए उस सकारात्मक परिवर्तन की कहानी है, जहां सरकारी योजनाएं कागजों से निकलकर लोगों के जीवन का हिस्सा बनीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विकास को केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से भी जोड़ा है। अयोध्या में भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास, उज्जैन में महाकाल लोक का सृजन और चारधाम परियोजना जैसे कार्य केवल अधोसंरचना विकास नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के प्रतीक हैं।

वर्ष 2014 से पहले जब देश पर आतंकवादी हमले होते थे, तब देशवासी केंद्र सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते थे, लेकिन अक्सर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख सीमित प्रतिक्रियाओं तक ही दिखाई देता था लेकिन 2014 के बाद यह तस्वीर बदली तो इसका कारण सिर्फ मोदी जी की नीतियां हैं। श्री मोदी जी का स्वाभिमान और साहस तो इस देश ने तब भी देखा था जब उन्होंने आतंकवादियों की धमकियों का सामना करते हुए कश्मीर के लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराया था। कश्मीर को धारा 370 के जाल से निकालकर भारतीय संविधान की मर्यादा में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय श्री मोदी जी द्वारा असंभव को संभव करने का एक अद्भुत उदाहरण है। इसके साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिन्दूर से आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक नीति ने दुनिया को यह संदेश दिया कि नया भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं दशकों से भारत माता की पीड़ा बने नक्सलवाद को समूल नाश करने के लिए श्री मोदी जी के प्रभावी अभियानों ने नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य को न सिर्फ साकार किया है बल्कि कभी नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम भी किया है।

एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौथे कार्यकाल के दौरान भारत विकसित राष्ट्र बनने की अपनी यात्रा को और अधिक गति देगा। देश की जनता ने पिछले वर्षों में जिस नेतृत्व, नीयत और परिणामों को देखा है, वह विश्वास आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत होगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत न केवल विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्तियों में शामिल होगा, बल्कि 21वीं सदी में मानवता को दिशा देने वाले राष्ट्र के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित करेगा।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

ब्रह्मा के कानों से दिशाओं की उत्पत्ति

महाशय चिम्मनलाल पुराण-तत्त्व-प्रकाश में फर्माते हैं कि वाराह-पुराण अध्याय 26 में लिखा है कि जब ब्रह्मा को चिन्ता हुई तब ब्रह्मा के कानों से दस दिशाएं उत्पन्न हुई।

प्रादुर्बभूवु: श्रोत्रेभ्यो दश कन्या महाप्रभा:।
पूर्वा च दक्षिणा चैव प्रतीची चोत्तरा तथा।।3।।

(लाला जी के खयालेशरीफ में यह लेख भी पुराणों की असम्भवता का एक नमूना है। शायद आपका कभी नीचे लिखे वेद मन्त्र से वास्ता नहीं पड़ा-)

(क) पद्भ्यां भूर्दिश: श्रोत्रात्तथालोकां
2।। अकल्पयन् ।
(यजु: 31 । 13)

(ख) दिशो मे श्रोगे श्रिता:
(तैत्तिरीय 3।10।8।6)

(ग) अथ यत्तच्छोत्रमासीत्ता इमा दिशोऽभवन्।
(जैमिनीयोपनिषद् 2।2।4)

(घ) यत्तच्छोत्रं दिश एव तत्।
(शतपथ 10 । 3।3।7)

अर्थात् (क) विराट् भगवान् के पाँवों से भूमि और श्रौत्र से दिशाओं की उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार अन्यान्य अङ्गों से लोकान्तर की रचना हुई।

(ख) दिशायें मेरे श्रोत्रेन्द्रिय के आश्रित हैं।

(ग-घ) विराट् भगवान् के श्रोत्र ही दिशायें हैं।

कहिये भद्रगुप्त जी! आपको कानों से दिशाओं का उत्पन्न होना ही असम्भव जंचता था परन्तु यजुर्वेद के इकत्तीसवें अध्याय में तो निराकार बाबा के अमुक अमुक अङ्गों से गाय, घोड़ा, गधा, भेड़, बकरी और आकाश-पाताल समस्त चराचर का उत्पन्न होना अङ्कित है। कदाचित् आपको निराकार के वचन भूत उपर्युक्त वेदमन्त्रों पर शंका करने की गुजाँइश हो तो

क्रमशः ...

'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस'

अतुल गोयल

बाल श्रम के खिलाफ हर साल 12 जून को 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2002 में बाल श्रम को रोकने के लिए जागरूकता और सक्रियता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इस वर्ष यह दिवस बाल श्रम के खिलाफ लाल कार्ड : बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, व्यस्कों के लिए सम्मानजनक काम' थीम के साथ मनाया जा रहा है, जो बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई और नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता का संचार करता है। बाल श्रम इतनी आसान समस्या नहीं है, जितनी लगती है। बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार के काम में शामिल करने का कार्य है बाल श्रम, जो उनके मौलिक अधिकारों को बाधित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में या किसी खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। बाल श्रम की समस्या केवल भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे विश्व में प्रचलित है। यह समस्या अफ्रीका और भारत सहित कई अविकसित या विकासशील देशों में प्रमुख है। बाल श्रम एशिया में 22 फीसदी, अफ्रीका में 32 फीसदी, लैटिन अमेरिका में 17 फीसदी, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और अन्य धनी देशों में 1 फीसदी है।

जब हम किसी रेस्तरां, टी-स्टॉल, होटल, कारखानों अथवा चूड़ी उद्योग में जाते हैं तो हम वहां 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आसानी से काम करते हुए देख सकते हैं। सुबह-सुबह घर-घर अखबार बांटना, सड़क किनारे जूते पॉलिश करना, कूड़े-कचरे के ढ़ेर में कागज-पॉलीथिन चुनना, 21वीं सदी में भी जब खेलने-कूदने और पढ़ने-लिखने की उम्र में लाखों बच्चों को ऐसे कार्यों के जरिये अपने परिवार के लिए आय जुटाते देखते हैं तो बहुत दुख होता है। इसके अलावा बीड़ी उद्योग, कालीन उद्योग, कांच, पीतल, ज्वैलरी उद्योग सहित कई अन्य खतरनाक काम-धंधों में भी मासूम बचपन हाड़-तोड़ मेहनत करते देखा जाता है। बाल श्रम न केवल उन्हें उनकी आवश्यक शिक्षा से वंचित कर रहा है बल्कि जिस अस्वच्छ वातावरण के तहत वे काम कर रहे हैं, वहां तरह-तरह की बीमारियां होने की संभावना भी कई गुना ज्यादा रहती है। ऐसे माहौल में काम करने वाले बच्चों को सांस की बीमारी, त्वचा रोग, दमा, टीबी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, कैंसर, कुपोषण, समय से पहले बुढ़ापा इत्यादि कुछ घातक बीमारियां होने की संभावना बढ़ने के अलावा यह समस्या राष्ट्र की प्रगति और विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में उभरती है। दरअसल देश की युवा पीढ़ी के कंधों पर ही देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बालश्रम जैसी समस्या के कारण वही प्रभावित होती है तो राष्ट्र के विकास की रफ्तार प्रभावित होना भी तय है। बाल श्रम की प्रथा के पीछे कई कारण हैं लेकिन इस मुद्दे की महत्वपूर्ण रीढ़ गरीबी ही है।

पीओके में सैन्य-पुलिस हिंसा के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ

कमलेश पांडे

पीओजेके में समय-समय पर सामने आने वाली हिंसा, दमन, विरोध-प्रदर्शन और मानवाधिकार संबंधी आरोप केवल स्थानीय घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इनके कई अंतरराष्ट्रीय आयाम भी हैं। चूंकि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में हाल के दिनों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों ने भारत सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। इसलिए सबने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार कई लोगों की मौत हुई, तथा बड़ी संख्या में लोग घायल हुए तथा गिरफ्तारियां और इंटरनेट प्रतिबंध जैसी कार्रवाइयाँ भी की गईं। लिहाजा यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय चिंता का भी सबब बन चुकी है।

जहां तक भारत की सधी हुई कड़ी प्रतिक्रिया की बात है तो भारत सरकार ने इस घटना पर सधी हुई कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कथित पुलिस बर्बरता और प्रदर्शनकारियों की मौतों पर चिंता जताते हुए कहा कि पाकिस्तान पीओके में अपने प्रशासनिक और राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए दमन का रास्ता अपना रहा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी इस स्थिति पर ध्यान देने और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की मांग की है।

जहां तक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, गिरफ्तारियों और इंटरनेट बंदी पर चिंता व्यक्त की तथा शांतिपूर्ण संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और कुछ कश्मीरी अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी पीओके में मानवाधिकारों की स्थिति पर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। जबकि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने घटनाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक असंतोष और नागरिक अधिकारों से जुड़े व्यापक संकट के रूप में प्रस्तुत किया है। लिहाजा, पीओजेके में होने वाली

बर्बर हिंसा के मायने केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके प्रभाव मानवाधिकार, भारत-पाकिस्तान संबंध, चीन की रणनीतिक परियोजनाओं, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तक फैलते हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं को केवल स्थानीय नहीं, बल्कि व्यापक भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाता है। आइए इसे विस्तार से इसके अंतरराष्ट्रीय मायने समझते हैं-

पहला, मानवाधिकारों का गम्भीर वैश्विक मुद्दा : यदि किसी क्षेत्र में नागरिकों पर अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध या राजनीतिक दमन के आरोप लगते हैं, तो यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक मंचों का विषय बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान ऐसे मामलों पर नजर रखते हैं।

दूसरा, पाकिस्तान की बर्बर अंतरराष्ट्रीय छवि पर प्रभाव: पीओजेके में अस्थिरता या हिंसा की खबरें अमेरिकी-चीनी पिल्ले पाकिस्तान के उस दावे को चुनौती दे सकती हैं कि वहां के लोग संतुष्ट और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत रह रहे हैं। इससे उसकी कूटनीतिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।

तीसरा, भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों पर असर: इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पहले से ही एक संवेदनशील मुद्दा है। पीओजेके में हिंसा की घटनाएं दोनों देशों के राजनीतिक विमर्श और कूटनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को और तेज कर सकती हैं।

चौथा, चीन की रणनीतिक चिंताएं: पीओजेके से होकर सीपीईसी (China-Pakistan Economic Corridor) का महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरता है। लिहाजा क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने पर चीन की आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं।

पांचवां, दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सुरक्षा: किसी भी संवेदनशील सीमा क्षेत्र में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहने से क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-निरोधक प्रयासों और सीमापार तनावों पर प्रभाव पड़ सकता है। इस कारण प्रमुख शक्तियां स्थिति पर नजर बनाए रखती हैं।

छठा, कश्मीर विमर्श का नया आयाम: पीओजेके में विरोध-प्रदर्शन या हिंसा की घटनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बहस भी जन्म देती हैं कि कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में लोगों की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाएं क्या हैं। इससे कश्मीर संबंधी वैश्विक विमर्श अधिक जटिल हो जाता है।

इसके राजनीतिक और कूटनीतिक मायने निम्नलिखित हैं- 1. पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियाँ उजागर हुई हैं — स्थानीय जनता के बीच शासन, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक अधिकारों को लेकर असंतोष सामने आया है। 2. भारत को कूटनीतिक अवसर मिला है — नई दिल्ली पीओके में मानवाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रश्न को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अधिक मजबूती से उठा सकती है। 3. कश्मीर विमर्श में नया आयाम — लंबे समय से भारत जिस मुद्दे को उठाता रहा है कि पीओके के लोगों को पर्याप्त राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हैं, उसे इस घटनाक्रम से नया बल मिला है। 4. अंतरराष्ट्रीय दबाव की संभावना — यदि हिंसा और दमन के आरोप बढ़ते हैं तो पाकिस्तान पर मानवाधिकारों के पालन को लेकर बाहरी दबाव बढ़ सकता है।

कुल मिलाकर, पीओके की यह हिंसा केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं रह गई है, बल्कि मानवाधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भारत-पाकिस्तान संबंधों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनती जा रही है।

अंततोगत्वा यह कहा जा सकता है कि इसके व्यापक राजनीतिक मायने ये हैं कि यदि पीओके में नागरिक असंतोष और दमन के आरोप बढ़ते हैं, तो पाकिस्तान की लोकतांत्रिक छवि, मानवाधिकार रिकॉर्ड और कश्मीर पर उसकी अंतरराष्ट्रीय दलीलों को चुनौती मिल सकती है। इसी कारण मुनीर की भूमिका पर बहस केवल सुरक्षा नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवाधिकार और राजनीतिक वैधता के प्रश्नों से भी जुड़ गई है।

आखिर मुनीर की तुलना डायर से क्यों की जा रही है? जनरल (अब फील्ड मार्शल) असीम मुनीर को जनरल डायर कहे जाने का संदर्भ हाल में पीओके में हुए प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई से जुड़ा है। यह तुलना कोई आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय निष्कर्ष नहीं है, बल्कि कुछ भारतीय राजनीतिक और सुरक्षा विश्लेषकों द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणी है।

जनरल डायर कौन थे?: Reginald Dyer ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे, जिन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यह घटना औपनिवेशिक दमन का प्रतीक मानी जाती है।

मुनीर की तुलना डायर से क्यों की जा रही है?: आलोचकों का आरोप है कि पीओके में आर्थिक और नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसमें कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में घायल होने की खबरें आईं। इसी आधार पर पूर्व जम्मू-कश्मीर डीजीपी एस.पी. वैद ने कहा कि पीओके आज जलियांवाला बाग जैसा दिख रहा है और आसिम मुनीर जनरल डायर की तरह व्यवहार कर रहे हैं।

उनके तर्क मुख्यत: तीन बिंदुओं पर आधारित हैं : निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोप। विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध और गिरफ्तारियां। असंतोष को राजनीतिक संवाद के बजाय सुरक्षा समस्या के रूप में देखना।

आज का इतिहास

1830 फ्रांस ने अल्जीरिया के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरु की थी।
1852 ताइपिंग विद्रोह: ताइपिंग बलों ने हुनान में प्रवेश किया।
1864 यूनियन जनरल उलेइसेस एस। ग्रांट ने अपने सैनिकों को वर्जीनिया के हनोवर काउंटी में कोल्ड हार्बर से निकाला, जो अमेरिकी गृहयुद्ध में सबसे खून से लथपथ लड़ाईयों में से एक था।
1889 रनवे यात्री गाड़ियां उत्तरी आयरलैंड के एक वर्तमान ट्रेननियर अराघ से टकराईं, जिसमें 80 लोग मारे गए।
1899 न्यू रिचमंड बवंडर ने संयुक्त राज्य के उत्तरी महान मैदानों में 117 लोगों की जान ले ली और 125 लोगों को घायल कर दिया।
1914 ग्रीक नरसंहार: फोकिया में ओटोमन यूनानियों को तुर्की अनियमित सैनिकों द्वारा जान से मारा गया।
1926 ब्राजील ने लीग ऑफ नेशन से बाहर आने का फैसला किया।
1939 बायरन नेल्सन ने यू.एस. ओपन जीता।
1942 अपने तेरहवें जन्मदिन पर, ऐनी फ्रैंक ने नीदरलैंड के नाजी कब्जे पर अपनी डायरी रखना शुरू कर दिया।
1952 तत्कालीन सोवियत संघ ने जापान के साथ शांति संधि को अवैध घोषित किया।
1954 पोप पायस XII ने डोमिनिक सैवियो की 14 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च में सबसे कम उम्र के गैर-शहीद संत बनाने के लिए उनकी मृत्यु हो गई।
1963 अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मेडगर एवर्स कू क्लक्स क्लान के सदस्य बायरन डी ला बेकविथ से थे।
1964 दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा।
1967 वेनेरा 4 लॉन्च किया गया था। वीनस शुक्र की खोज के लिए सोवियत वेनेरा कार्यक्रम में एक जांच थी। किसी अन्य ग्रह के वातावरण का इन-प्लेस विश्लेषण करने के लिए यह पहली सफल जांच थी। यह किसी दूसरे ग्रह पर उतरने की पहली जांच भी हो सकती है।
1968 यू.एस. में रोज़मरी की बेबी फिल्म का प्रकाशन किया गया।
1987 शीत युद्ध- बर्लिन की दीवार द्वारा बर्लिन के ब्रेंडेन बर्गर गेट पर एक भाषण के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव को %इस दीवार को फाड़ने% की चुनौती दी!
1990 रूस दिवस 12 जून को मनाया जाता है, जो रूसी संघ का राष्ट्रीय अवकाश है। यह 1992 से हर साल मनाया जाता है।
1991 बोरिस येल्तसिन तत्कालीन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बनें।

क्षत्रपों की हार से भाजपा हुई ताकतवर तो कांग्रेस को मिला नेतृत्व का नया अवसर

विनोद अग्निहोत्री

एक-एक करके ज्यादातर क्षेत्रीय क्षत्रपों की चुनावी शिकस्त के बाद आखिरकार लंबे समय के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई और शुरुआती गिले-शिकवे के बाद सबने एक बार फिर एकजुट होकर पांच मुद्दों पर सरकार को घेरने का एलान किया। जिस समय ये बैठक हो रही थी करीब उसी समय तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 सांसदों ने संसद में पार्टी से अलग होकर एनडीए के साथ जाने का फैसला भी कर लिया। पहले विधायक दल और अब लोकसभा में संसदीय दल की टूट ने ममता बनर्जी को और कमजोर कर दिया है। लेकिन बैठक में जिस तरह ममता को हाथों-हाथ लिया गया उससे संकेत है कि विपक्ष उनके लड़ाकू तेवरों का राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करेगा। ममता के सामने भी इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है कि वह कांग्रेस के साथ कदमताल करके राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखें।

चर्चा या अटकलें कांग्रेस में तृणमूल में विलय की भी चल रही हैं लेकिन फिलहाल अभी इस पर कोई ठोस बातचीत दोनों दलों के बीच नहीं हुई है। लेकिन सोनिया के साथ ममता के आत्मीय रिश्ते इसके लिए जमीन तैयार कर सकते हैं। विपक्षी दलों की यह कवायद अगर सड़क पर एकजुट संघर्ष के रूप में विकसित नहीं होती है तो सिर्फ नेताओं की फौरी एकता से कुछ खास होने वाला नहीं है। जब तक अपने पांच मुद्दों पर सारे विपक्षी दल सड़क पर ईमानदारी से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर नहीं उतारते तब तक उनके जनाधार और कार्यकर्ताओं की एकता व्यवहारिक नहीं होगी और इंडिया गठबंधन सिर्फ नेताओं की चाय पार्टी से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। फिलहाल क्षत्रपों की हार से भाजपा और एनडीए सरकार को नई ताकत मिली है तो विपक्षी गठबंधन में अपना नेतृत्व स्थापित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है।

बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायक दल और बाद लोकसभा में संसदीय दल में टूट ने विपक्ष के क्षेत्रीय किलों में सबसे मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया है। इसके पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की शर्मनाक हार से शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के किले भी ढह चुके थे। कांग्रेस वैसे भी यहां विपक्षी राजनीति में एक तिहाई हिस्सेदार ही है। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार ने अरविंद केजरीवाल की चमक को धुंधला कर दिया। अब पंजाब ही फिलहाल आप का सहारा है। बंगाल से पहले बिहार में भी राजद कांग्रेस वामदलों के महागठबंधन को महज 35 सीटों पर समेट कर एनडीए ने जबरदस्त जीत दर्ज की और अब वहां भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहली बार अपनी सरकार बनाई है और जनता दल यूनाइटेड अब वहां महज साझीदार है। तमिलनाडु में फिल्म स्टार थलपति विजय की टीवीके के हाथों सत्तारूढ़ डीएमके की हार

और उसके बाद कांग्रेस का टीवीके सरकार में शामिल होने से विपक्ष के एक और बड़े छत्रप को गद्दी से उतार दिया। कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एक मजबूत क्षेत्रीय दल के रूप में भाजपा को 2027 के विधानसभा चुनावों में चुनौती देगी और पंजाब में आम आदमी पार्टी को अपने बचे हुए किले को बचाने की चुनौती है।

अब सवाल ये है कि लगातार होते जा रहे अपने क्षत्रपों के पराभव के बाद देश में विपक्ष की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी। 2023 में भाजपा सरकार के खिलाफ बना विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अब सिर्फ नाम के लिए ही बचा है। इसके प्रणेता नीतीश कुमार सबसे पहले अलग हुए फिर उनका अनुसरण रालोद के जयंत चौधरी ने किया। दोनों ने एनडीए की शान और ताकत दोनों बढ़ाई ।लोकसभा चुनावों में भी इंडिया गठबंधन किसी गठबंधन की तरह चुनाव नहीं लड़ा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को खड़ा ही नहीं होने दिया और वहां कांग्रेस वाम मोर्चा तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने थे जबकि दिल्ली में उनका गठबंधन था। केरल में वाम मोर्चा और कांग्रेस नीत यूडीएफ के बीच सीधा मुकाबला था। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने तुरंत खुद को इंडिया गठबंधन से बाहर किया। अब तमिलनाडु में डीएमके ने खुद को इससे अलग कर लिया है और टीवीके ने अभी तक इंडिया गठबंधन में आने की कोई घोषणा नहीं की है।

उधर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला न सिर्फ ढहा है बल्कि तृणमूल कांग्रेस के करीब साठ विधायकों ने ममता के फैसले के खिलाफ निष्कासित विधायक ऋब्राब्रत बनर्जी को सदन में अपना नेता चुनकर विधानसभा अध्यक्ष से इसकी मंजूरी भी ले ली है। यह दल विभाजन के महाराष्ट्र मॉडल से थोड़ा अलग है। हालांकि इसमें भी महाराष्ट्र की तरह बागी खेमा ममता बनर्जी को ही अपना नेता बता रहा है जैसा कि महाराष्ट्र में अजित पवार और उद्धव खेमों ने अलग होने के बावजूद शरद पवार और बाला साहब ठाकरे को अपना नेता बताया था। लेकिन जहां महाराष्ट्र में विभाजन के बाद दोनों खेमे सत्तारूढ़ भाजपा के साथ सरकार में शामिल हो गए लेकिन पश्चिम बंगाल में बागी खेमा विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में ही रहना चाहता है। दल विभाजन का यह नया बंगाल मॉडल है। तमिलनाडु में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने भाजपा से अलग होकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने का एलान किया है।

इन तमाम बदलते हालात में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और एनडीए से बाहर दूसरे क्षेत्रीय दलों के सामने दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि वो कथित इंडिया गठबंधन ऐसे ही ढीले-ढाले अंदाज में चलाते रहें और अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को जूनियर साझेदार बनाकर पहले की तरह भाजपा और एनडीए से लड़ते हुए अपने लिए नई संभावनाएं तलाशें और कांग्रेस भी किसी राष्ट्रीय गठबंधन की बजाय 2004 के राजनीतिक मॉडल पर चलते हुए राज्यवार अलग-अलग दलों के साथ अपने गठबंधन और सीटों के तालमेल करे। फिर 2029 के चुनावों में अधिकतम सीटों पर लड़कर अगर सरकार बनाने की नौबत आए तब यूपीए जैसा चुनाव बाद कोई राष्ट्रीय गठबंधन बनाए। दूसरा रास्ता है कि सभी क्षेत्रीय दल कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करके राहुल गांधी को अपना नेता मानें और एक समान साझा कार्यक्रम तैयार करके आगे होने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों की एकजुट होकर तैयारी करें।

इंडिया गठबंधन या जो भी इसका नाम दिया जाए उसका एक मुकम्मल ढांचा बनाए और सारे चुनाव अलग-अलग न लड़कर पूरी तरह एकजुट होकर लड़े जाएं। इससे जनता में विपक्षी गठबंधन की साख बनेगी और भाजपा व एनडीए विरोधी मतदाता इसे एक मुकम्मल विकल्प के रूप में देख सकेंगे। अगर कांग्रेस समेत सारे घटक दल ईमानदारी से इस पर अमल करेंगे, तब जाकर 2029 तक भाजपा नीत एनडीए सरकार के मुकाबले के लिए कोई राजनीतिक विकल्प तैयार हो सकेगा। लेकिन उसके पहले विपक्षी गठबंधन 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। कांग्रेस को पंजाब, उत्तराखंड चुनाव जीतने होंगे और हिमाचल में अपनी सरकार फिर बनानी होगी। वहीं गुजरात में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। जबकि उत्तर प्रदेश में सपा-कांग्रेस को हर हालत में चुनावी जीत दर्ज करानी होगी। इसके बाद 2028 में होने वाले कर्नाटक व तेलंगाना में कांग्रेस को अपनी सरकारें वापस लानी होंगी और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीतने के लिए पूरा जोर लगाना होगा। तब जाकर वह 2029 में भाजपा के मुकाबले तन कर खड़ी हो सकेगी और भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व कर सकेगी।

भाजपा और उसके सहयोगी दलों से ज्यादा यह बात विपक्षी क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने कहनी शुरू की और यह मांग उठने लगी कि कांग्रेस की जगह विपक्षी इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी जैसी मजबूत लड़ाकू नेता को सौंपी जाए। यह मांग अरविंद केजरीवाल ने शुरू की और इसे दबी जुबान से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने भी स्वर दिया। सिर्फ इस मुद्दे पर स्टालिन चुप रहे। कांग्रेस के पास भी इसका कोई माकूल जवाब नहीं था, इसलिए उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी के सिवा सारे क्षेत्रीय दल भाजपा से सीधी लड़ाई में परास्त हुए और तमिलनाडु में डीएमके को एक नए दल ने हरा दिया तो क्षेत्रीय क्षत्रपों के सुर भी नरम हो गए

मानसून सत्र और राजनीति का समुद्र मंथन

सनत जैन

जुलाई माह में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराहट देखने को मिल सकती है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। पिछले सत्र में परिसीमन बिल सरकार संसद में पास नहीं करा पाई थी। बीते महीनों में जिस तरह से सरकार को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, विदेशी निवेशक शेयर बाजार से निवेश किया धन वापस निकाल रहे हैं। कच्चे तेल के आयात से सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ऐसी स्थिति में सरकार मानसून सत्र में कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। देश में खाद्य पदार्थों, ईंधन और घरेलू जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों को लेकर जनता के बड़े वर्ग में नाराजगी दिखाई दे रही है। किसान संगठन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), फसल खरीद और कृषि लागत जैसे मुद्दों पर आंदोलित हैं। वहीं नीट पेपर लीक से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र संगठनों की ओर से सड़क पर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। काकरोच के नाम पर युवा जेन-जी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है।

विपक्षी दलों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सरकार के दबाब में काम करने के आरोप हैं। जबकि सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। सरकार अपने कार्यकाल में हुए विकासकार्यों, कल्याणकारी योजनाओं तथा आर्थिक उपलब्धियों को सामने रखती है। राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती बयानबाजी ने संसद के आगामी सत्र को और महत्वपूर्ण बना दिया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही संसद सत्र के पहले अपने-अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं। क्षेत्रीय दलों की भूमिका इस बार विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद का मानसून सत्र आने वाले विधानसभा चुनावों और भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में यह मानसून सत्र सरकार के लिए संकटभरा हो सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को यदि समुद्र मंथन की उपमा दी जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। समुद्र मंथन में जिस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष के साथ-साथ सहयोग भी था, उसी प्रकार भारतीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उस पौराणिक कथा में पहले विष निकला और अंत में अमृत प्राप्त हुआ था। लोकतंत्र के इस राजनीतिक मंथन से मानसून सत्र में कौन लाभान्वित होगा और किसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मानसून सत्र केवल विधायी कार्यवाही का मंच नहीं रहेगा, बल्कि यह सरकार की नीतियों, विपक्ष की रणनीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर व्यापक राजनीतिक बहस का केंद्र बनने जा रहा है। इस राजनीतिक समुद्र मंथन का परिणाम क्या होगा, इसका निर्णय अंततः जनता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं ही तय करेंगी। जिस तरह से सत्ता पक्ष ने लोकसभा एवं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 6 सांसदों इसके बाद टीएमसी के सांसदों को पार्टी से अलग होकर अलग गुट बनाने या सांसदों से इस्तीफा दिलवाकर विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत है, मानसून सत्र में सरकार कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। इसके लिए सरकार किसी भी स्तर पर अपने आपको सुरक्षित करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। इसका एक संदेश यह भी है, सरकार अंदर से कमजोर है। भाजपा के अंदर से भी असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने चारों ओर से सुरक्षित रहने के लिए घेराबंदी शुरु कर दी है।

लोगों का भरोसा जीतने में सफल रहे हैं पीएम मोदी

नीतीश कुमार

भारत जैसे विशाल और प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र में जनता का भरोसा जीतना कठिन होता है और इसे बनाये रखना और भी कठिन काम है। लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और जनता की कड़ी नजर के बावजूद नरेंद्र मोदी लोगों का विश्वास बनाये रखने में सफल रहे हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति में एक नया मानक स्थापित किया है। हालांकि हम भारत के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और मैं उस पीढ़ी से हैं, जिनकी राजनीतिक चेतना आपातकाल से प्रभावित हुई थी। हमने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर हुए हमले को अपनी आंखों से देखा और उस आंदोलन में भाग लिया।

दशकों तक यह धारणा रही कि देश के सर्वोच्च पद कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों या प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में जन्म लिये लोगों के लिए आरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने इस धारणा को चुनौती दी है। साधारण शुरुआत से उठकर देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद तक पहुंचने वाले मोदी लाखों युवा भारतीयों के लिए प्रेरणास्रोत बन गये हैं। उनकी कहानी इस विश्वास को और सुदृढ़ करती है कि एक जीवंत लोकतंत्र में संकल्प, कड़ी मेहनत और क्षमता, जन्म और परिस्थिति की बाधाओं को पार कर सकती हैं। इस दृष्टि से यह कामयाबी न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत और खुलेपन का एक शक्तिशाली सबूत भी है।

लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने और सम्मान का जीवन जीने में मदद करना किसी भी राजनीतिक नेता की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस लिहाज से पीएम मोदी का रिकॉर्ड शानदार रहा है। गरीबी उन्मूलन पर उनका विशेष ध्यान रहा है, जिसके फलस्वरूप एनडीए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। शौचालय, बैंक खाते, घर, गैस कनेक्शन, नल से जल आपूर्ति, स्वास्थ्य बीमा कवरेज तथा अनेक मूलभूत आवश्यकताएं करोड़ों लोगों तक पहुंची हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों,

महिलाओं, गरीब परिवारों और विकास कार्यक्रमों के पहली पीढ़ी के लाभार्थियों के बड़े वर्ग ने खुद को भारत की विकास गाथा में सक्रिय भागीदार के रूप में देखना शुरू कर दिया है। युवाओं को विशेष योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता के नये अवसर मिले हैं।

उनकी कई योजनाओं से महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ हुआ है और उनके दैनिक जीवन की मुश्किलें कम हुई हैं। बिहार में मेरा अनुभव रहा है कि जब महिलाओं को विकास कार्यों के केंद्र में रखा जाता है, तो समाज तेजी से प्रगति करता है। बिहार में हमारे जीविका प्रयोग की सफलता की चर्चा अब दुनियाभर में हो रही है। कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के नाते मैं जानता हूं कि लाभ को इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी यह सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं कि शासन का परिणाम नागरिकों के लिए वास्तविक लाभ में बदल जाये। उन्होंने हमेशा दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और मजबूत निगरानी तंत्रों के माध्यम से नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच का अंतर काफी कम हो गया है।

प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक यात्रा में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लंबा और सफल कार्यकाल शामिल है। वास्तव में, वह जल्द ही चुनी हुई सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लेंगे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस अनुभव ने उन्हें राज्यों की जरूरतों और उनका समर्थन करने के महत्व की गहरी समझ दी है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सहकारी संघवाद के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों की परवाह किये बिना बिहार के विकास के लिए समर्थन दिया। मैं विशेष रूप से 2024-25 और 2025-26 के बजट के दौरान बिहार को मिले अद्भुत समर्थन का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें मखाना बोर्ड और भागलपुर में विद्युत संयंत्र की स्थापना, बाढ़ प्रबंधन के लिए कोष और कई अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निधि शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के मन में बिहार की अनोखी संस्कृति और परंपराओं का बहुत सम्मान है। उन्होंने मखाना, मधुबनी चित्रकला और राज्य के अन्य उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को उपहारस्वरूप देकर बिहार की धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया है। उन्होंने ही सुनिश्चित किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाये। पिछले दशक में बिहार को कई बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं से लाभ हुआ है। वर्ष 2014 से पहले की तुलना में केंद्र से समर्थन और निवेश में काफी वृद्धि हुई है। गंगा पर महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, हवाई अड्डों का विकास और रेलवे अवसंरचना का तेजी से उन्नयन बिहार की विकास गति को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में रेलवे विद्युतीकरण और अन्य आधुनिकीकरण परियोजनाओं ने असाधारण गति प्राप्त की है।

मैंने हमेशा भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता का समर्थन किया है। पीएम मोदी की जिन खूबियों ने उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया है, उनमें से एक है उनका बेदाग रिकॉर्ड और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका मजबूत रुख। संस्थागत सुधारों के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने के साथ उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के जरिये भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी दिखाई है। पीएम मोदी के कार्यकाल में वैश्विक मंच पर भारत का महत्व बढ़ा है। एक भारतीय के रूप में मुझे इस बात पर गर्व होता है कि अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, तकनीक, स्वास्थ्य या सहयोग जैसे मामलों में हमारी बात का स्वागत किया जाता है।

इंडिया गठबंधन में दरारें : एकता बनाम बिखराव

पूनम आई. कौशिश

दलबदल, आहत अहंकार और टूटी वफादारी के इस दौर में, हालिया राज्य चुनावों में तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और माकपा की हार और निराशा के कारण विपक्ष के 'इंडिया' ब्लॉक में दरारें और गहरी हो गईं। कल 25 विपक्षी दलों की बैठक में अंदरूनी मतभेद और तनाव और बढ़ गए। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव जैसे मुद्दों पर भाजपा-विरोधी रुख बनाए रखने के बावजूद गठबंधन की एकता बहुत कमजोर स्थिति में है। यह सब राहुल गांधी के 'एकजुट रहने पर हम टिके रहेंगे, बंटने पर गिर जाएंगे' के आह्वान के बावजूद हो रहा है। निश्चित रूप से, गठबंधन में कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका पर दबाव बढ़ा है और कुछ सहयोगी दल खुले तौर पर उसके रवैए पर सवाल उठा रहे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई, जब द्रमुक ने घोषणा की कि वह लंबे समय से सहयोगी रही कांग्रेस के साथ जगह सांझा करने को तैयार नहीं, जिसने द्रमुक से संबंध तोड़कर विजय की टी.वी.के. से हाथ मिलाया और तमिलनाडु में उनकी सरकार का हिस्सा बनी। आम आदमी पार्टी और विजय की टी.वी.के. भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं।

जहां झामुमो झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों में से 1 के लिए कांग्रेस द्वारा एकतरफा उम्मीदवार घोषित करने से नाराज है, वहीं माकपा ने पूर्व मुख्यमंत्री विजयन पर हमलों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। पश्चिम बंगाल में ममता की तृणमूल कांग्रेस और संसद में बागी संकट के बीच, जहां 59 विधायक और 20 सांसद अलग हो गए हैं, वह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आगे की राह तय करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक अस्तित्व संवैधानिक सत्ता बनाए रखने पर टिका है। कांग्रेस भी तृणमूल कांग्रेस के संकट पर नजर रखे हुए है। तृणमूल कांग्रेस का मामला उन क्षेत्रीय दलों के लिए पीढ़ीगत संकट को उजागर करता है, जिन्होंने पिछले 3 दशकों में करिश्माई नेताओं

की बदौलत असाधारण सफलता हासिल की थी, लेकिन अब वे अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। राजद, बीजद, तृणमूल कांग्रेस, शिव सेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और द्रमुक जैसी पार्टियां, जो एक मजबूत नेता के इर्द-गिर्द एकजुट होकर बची रहीं, आज उनके सामने एक कठिन विकल्प है, या तो किसी चुने हुए उत्तराधिकारी को कमान सौंपकर बगावत को न्यौता दें, या फिर अपने संस्थापक परिवारों से किनारा कर पार्टी के बिखरने का जोखिम उठाएं।

राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते, क्षेत्रीय पार्टियों को संसद में परिसीमन, संघवाद और केंद्र-राज्य संबंधों जैसे मुद्दों पर उसके साथ तालमेल बिठाना होगा। हालांकि, साथ ही क्षेत्रीय पार्टियां अधिक मुखर भी हो रही हैं। द्रमुक का अलग होना और माकपा की सार्वजनिक आलोचना यह दिखाती है कि सहयोगी दल अब कांग्रेस को गठबंधन के निर्विवाद नेता के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। इसके अलावा, राज्य-स्तरीय प्रतिद्वंद्विताएं भी अनसुलझी हैं। कांग्रेस केरल में माकपा और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सीधे मुकाबले में है। उत्तर प्रदेश में उसकी और समाजवादी पार्टी की प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हैं और अन्य जगहों पर भी सहयोगियों के साथ उसका टकराव है। इस प्रकार, ये विरोधाभास हमेशा से गठबंधन की संरचनात्मक कमजोरी रहे हैं। जहां तक पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिलेश की सपा या लालू की राजद की बात है, तो गठबंधन को जीवित रखने के लिए उनके पास सबसे मजबूत कारण हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में विपक्ष की एकता पर काफी हद तक निर्भर है, जहां वह कांग्रेस और ठाकरे की शिव सेना (उद्धव) के साथ मिलकर काम करती है। पवार ने ऐतिहासिक रूप से गठबंधन तोडने वाले की बजाय गठबंधन बनाने वाले की भूमिका निभाई है।

सपा को कांग्रेस के साथ तालमेल से बार-बार फायदा हुआ है और वह गठबंधन की केंद्रीय हस्तियों में से एक बनी हुई है। राजद के लिए, राजग के खिलाफ कांग्रेस एक जरूरी सहयोगी है, क्योंकि अलग होने से बिहार में विपक्ष कमजोर हो जाएगा। आगे की बात करें तो 3 मुख्य संभावनाएं हैं-पुनर्गठन, न कि पूरी तरह खत्म होना-भले ही कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी हुई है, लेकिन सपा, राजद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, झामुमो जैसी क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा आजादी चाह सकती हैं। दूसरी, एक ढीला-ढाला संसदीय मोर्चा-पार्टियां संसद के अंदर तो तालमेल बनाए रखें लेकिन राज्य चुनावों में अलग-अलग लड़ें। तीसरी, क्षेत्रीय पार्टियां ऐसे गठबंधन ढांचे की मांग के लिए एकजुट हो सकती हैं जो कांग्रेस पर कम केंद्रित हो। यह 'असहमति के बावजूद एकता' वाला मामला है, न कि 'बिखराव में एकता' वाला। क्या यह एक सार्थक राष्ट्रीय गठबंधन के तौर पर टिक पाएगा, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि क्या कांग्रेस द्रमुक, माकपा, झामुमो, और तृणमूल कांग्रेस के साथ रिश्ते सुधार सकती है और गठबंधन को बनाए रखने के लिए मोदी के नेतृत्व वाले राजद को चुनौती देने के एक सांझा लक्ष्य पर कायम रह सकती है? साफ है कि विपक्ष को ऐसी भाषा और तरीका खोजना होगा, जो भाजपा की कुशलता, अलग-अलग आवाजों को उठाने की क्षमता, चुनाव लडने की जबरदस्त मशीनरी और उन संसाधनों का मुकाबला कर सके, जिनके दम पर वह अपनी संचार-प्रधानता और छवि बनाए रखती है। निश्चित रूप से, आने वाले दिनों में नैरेटिव कैसे आगे बढ़ता है, इस पर नजर रहेगी।

ममता अपनी आखिरी चाल से क्या बदल सकती हैं राजनीतिक समीकरण!

सत्येंद्र प्रताप सिंह

राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक संभावना को लेकर चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। हालांकि चर्चा केवल उनके या अभिषेक बनर्जी के व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस में जाने की नहीं है, बल्कि यह संभावना भी जताई जा रही है कि तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कराया जा सकता है। कल्पना कीजिए, राजनीति का कितना विचित्र परिहास है! जिसने न केवल कांग्रेस से अलग होकर अपनी राह बनाई थी, बल्कि गर्व के साथ कहा करती थीं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को महज एक साइन बोर्ड बनाकर छोड़ दिया है, वही आज सांसद, विधायक, पार्षद, राज्य की सत्ता और मुख्यमंत्री की कुर्सी, सब कुछ खोने के बाद कथित तौर पर उसी कांग्रेस के साइन बोर्ड के नीचे आश्रय तलाश रही हैं। हालांकि, इस मामले में भी पश्चिम बंगाल में यह पहला होने का श्रेय तृणमूल कांग्रेस को नहीं दिया जा सकता। यदि कांग्रेस से अलग होकर बने किसी दल का अंततः फिर कांग्रेस में विलय हो जाता है, तो यह कोई नई राजनीतिक घटना नहीं होगी। इससे पहले अजय मुखोपाध्याय की बांग्ला कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस भी कांग्रेस से अलग होकर बनी थीं, लेकिन बाद में कांग्रेस की मुख्यधारा में वापस शामिल हो गई थीं। इसलिए ऐसा घटनाक्रम भारतीय राजनीति, विशेषकर पश्चिम बंगाल की राजनीति, में पहले भी देखा जा चुका है। खैर, यदि ऐसा होता है, तो इसके दूरगामी राजनीतिक और कानूनी प्रभाव हो सकते हैं। किसी राजनीतिक दल का विलय केवल सांसदों या विधायकों की इच्छा से नहीं होता। इसके लिए पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। कांग्रेस के संविधान की तर्ज पर बने तृणमूल कांग्रेस के संविधान में भी ऐसी व्यवस्था मौजूद है। यदि पार्टी के प्रतिनिधि (डेलिगेट्स), जिनकी संख्या लगभग एक हजार बताई जाती है, बैठक में बहुमत से विलय का प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो नियमों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वतः कांग्रेस के जनप्रतिनिधि माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल के 80 और कांग्रेस के 2 विधायक मिलकर कांग्रेस की संख्या 82 तक पहुंचा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से, तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट सांसद और विधायक इस निर्णय को स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। विधानसभा में उनके पास यदि दो-तिहाई बहुमत मौजूद है, तो वे अलग समूह बनाकर राजनीतिक रास्ता चुन सकते हैं। 82 विधायकों की संख्या में दो-तिहाई का आंकड़ा 55 होता है, और यदि असंतुष्ट खेमे के पास इससे अधिक विधायक हैं, तो उनके लिए अलग राह चुनना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। लेकिन लोकसभा में स्थिति अलग होगी। यदि तृणमूल के 28 सांसद कांग्रेस सांसद माने जाने लगें, तो कांग्रेस की कुल संख्या 127 तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 85 सांसद होगा, जिसे हासिल करना असंतुष्टों के लिए कठिन साबित हो सकता है। परिणामस्वरूप वे दल-बदल विरोधी कानून की बाधाओं में फंस सकते हैं। उनके पास इस्तीफा देने का विकल्प तो रहेगा, लेकिन वे तृणमूल कांग्रेस के नाम, चुनाव चिन्ह या संगठनात्मक संसाधनों पर दावा नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह राजनीतिक प्रतिशोध की चाल होगी, अस्तित्व बचाने का प्रयास, या फिर अपनी राजनीतिक विरासत और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनाई गई एक रणनीति? आने वाले समय में इसका जवाब पश्चिम बंगाल की राजनीति की नई दिशा तय कर सकता है।

हरड़ का सेवन रखें शरीर को तंदुरुस्त

हरड़ त्रिफला चूर्ण से बनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। यह कई प्रकार से सेहत के लिए लाभकारी होती हैं। इसे हरीतकी भी कहा जाता है। इसके सेवन से बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता हैं। हरड़ पेट को साफ करने और पाचन तंत्र को सुधार कर इसे मजबूत करने का काम करती है। आयुर्वेद के अनुसार यह जड़ी-बूटी पोषक तत्वों का अच्छे से समावेश कर शरीर को स्वस्थ बनाती है।

इन कारणों से हो सकता है ब्रेन ट्यूमर

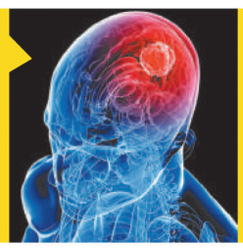

सिरदर्द होना आम बात है, जिसे लोग हमेशा हलके में लेते है। लेकिन ये सिर दर्द आपके ब्रेन ट्यूमर का कारण बन सकता है। यदि ऐसे स्थिति से आप गुजर रहे है तो तुरंत जांच कराएं अगर आपको सुबह उठकर उबकी या उल्टियां आती है, तो इसे हलके में बिल्कुल न लें। जब शरीर में मूवमेंट करने के दिक्कत आ रही हो, तो तुरंत जाकर जांच करवाइए। ऐसा तब होता है जब सेरिबैलम में ट्यूमर पनपने लगता है।

पैरों व टखनों की सूजन कम करने के उपाय

पैरों या टखनों की सूजन एक आम समस्या है जो कई कारणों से हो सकती है। इस समस्या में पैरों में सूजन व काफी दर्द होता है। इससे निपटने के लिए घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे गर्म पानी में पैर डुबोना, तेल मालिश, बर्फ की मसाज आदि।

इन कारणों से होती है सूजन

पैर व टखनों की नसों में होने वाली सूजन को टेन्डोनिटिस कहा जाता है। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसमें पैर, खासतौर पर टखनों और एड़ियों के आसपास सूजन, लालिमा और जलन हो जाती है। यह समस्या पैर के निचले हिस्से में भारी दबाव के कारण पैदा होती है। कई बार यह गलत साइज के जूते पहनने से, मोटापे से, गर्भावस्था में, ठोकर लगने से या शुगर के कारण भी यह समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरुरत नहीं। आप कुछ आसान प्राकृतिक व घरेलू उपाय अपनाकर भी पैरों व एड़ियों की सूजन से निजात पा सकते हैं।

गर्म तेल से मालिश

कटोरी में थोड़ा तेल लें, तवे पर रखकर उसे गर्म कर लें। इस तेल से पैर की मसाज करें। मसाज हल्के हाथों से, कुछ मिनटों के लिए करें। इससे प्रभावित नसों में रक्त का संचार होगा और दर्द दूर होगा और आपको आराम मिलेगा। जब तक सूजन बनी रहे, दिन में दो से तीन बार इस तरह से मसाज करें। इस मसाज के लिए आप जैतून या नारियल के तेल का इस्तेमाल करें। ये ध्यान रखे मालिश के सयम कमरें का तापमान सामान्य हो। एसी या ठंडे वातावरण में मालिश ना करें।

सिरके का उपयोग

पैर का दर्द और सूजन सिरके से भी कम कर सकते हैं। सामान मात्रा में पानी और सिरका मिलाकर इस कुछ देर तक गर्म करें और इसमें एक मुलायम मलमल या फिर सूती का कपड़ा डालकर दर्द वाली जगह पर लगाएं। इस प्रक्रिया को दिन में दो से तीन बार करें और बाद में इसे पोंछकर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं।

बर्फ की सेंक

बर्फ की सेंक टखने की सूजन और दर्द को दूर करने के लिए एक कारगर घरेलू उपाय है। इसके लिए, कुछ बर्फ के टुकड़े लें और उसे बेलन या किसी और चीज की सहायता से तोड़ लें। फिर एक बैग में रखकर कॉटन के टॉवेल में लपेट लें। इस बैग को दर्द वाली जगह पर रखें। इससे सूजन और दर्द दोनों कम होंगे। एक बार में आप इस बैग को 15 मिनट तक रख सकते हैं। ज्यादा आराम के लिए इसे दिन में कई बार इस्तेमाल करें।

गर्म पानी और नमक

फुट टेन्डोनिटिस में गर्म पानी और सेंधा नमक भी कारगर है। गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए अपना पैर इसमें रखें। पानी की गर्माहट दर्द को खीच लेगी और सेंधे नमक से शरीर में मैग्नीशियम की पूर्ति होगी। पैर को ड्राईनेस से बचाने के लिए इस प्रक्रिया को दिन में एक बार ही करें। इसके बाद गीलेपन को पोंछ लें। इस पानी में खुशबू वाले तेल की कुछ बूंदे भी डाल सकते हैं।

आटा

आटा ऐसी चीज है जो हर किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आटा गर्माहट देने वाला होता है, इसकी गर्माहट से दर्द से जल्दी राहत मिल जाती है। आटे और वाइन का पेस्ट बना कर तीस मिनट तक दर्द वाली जगह पर लगाएं। उसके बाद गुनगुने पानी से इसे धोकर हल्की मसाज के साथ मॉइस्चराइजर लगाएं।

लहसुन

रोज लहसुन या फिर लहसुन के तेल वाली कैप्सूल खाने से टखनों और पैरों की सूजन कम होने लगती है। अपने खाने में लहसुन मिलाएं या फिर ऐसे ही लहसुन की कली चबाएं। आप देखेंगे कि इसका असर तुरंत होता है।

बॉल के साथ एक्सरसाइज

जूते को खोलकर आराम से बैठ जाएं। उसके बाद गोल्फ की गेंद के ऊपर बारी-बारी से पैरों को रख कर धीरे-धीरे गेंद को गोलाकर गति में घुमाते हुए दबायें। इस व्यायाम से पैरों का दर्द कुछ देर के बाद कम होने लगेगा। इस व्यायाम से पैरों की मांसपेशियों को भी जान मिलती है।

लिंफ नोड्स की सूजन हटाएं

लिंफ नोड में अगर सूजन आ गई है तो शरीर में दूसरी समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं, लिंफ नोड की सूजन कम करने के लिए आपके घर में कौन से घरेलू नुस्खे मौजूद हैं, इसके बारे में इस स्लाइडशो में जानते हैं।

क्यों है लिंफ नोड में सूजन

लिंफ नोड्स एक नहीं कई ग्रंथियां होती हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे - जबड़े के पीछे, आर्मपिट, कान के पीछे, कान के पीछे, सिर के पीछे, आदि अंगों में होता है। इसका प्रमुख काम इम्यून सिस्टम को सुचारु करना है जिससे शरीर हानिकारक कीटाणुओं से लड़ सकता है। लेकिन किसी कारण से लिंफ नोड्स में सूजन हो जाती है, इस समस्या को लिंफेडेनोपैथी या लिंफैडेनिटिस कहते हैं। इसके कारण शरीर के दूसरे अंगों में संक्रमण भी हो सकता है। इसके अलावा कोल्ड, टांसिल, जिंजिवाइटिस, त्वचा में संक्रमण, आदि समस्याएं भी हो सकती हैं। लिंफ नोड्स की सूजन कम करने के लिए आप घरेलू नूस्खों को आजमा सकते हैं। इस स्लाइडशो में उन नुस्खों के बारे में बता रहे हैं।

गरम पानी से सिंकाई

लिंफ नोड्स में सूजन कम करने के लिए गरम पानी से सिंकाई कीजिए। जब गरम तापमान का संपर्क शरीर के दूसरे अंगों से होता है तब शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है और सूजन कम हो जाती है। इसके लिए पानी को गरम कीजिए और उसमें एक साफ कपड़े को भिगोकर सूजन वाली जगह पर 5 से 10 मिनट के लिए रखें। जब तक सूजन समाप्त न हो जाए इस क्रिया को दिन में कई बार दोहराएं। गरम पानी से सूजन वाली जगह की सफाई भी कर सकते हैं।

नमक पानी

गले में या जबड़े में पाई जाने वाली लिंफ नोड में सूजन है तो नमक पानी का गरारा करने से जल्द आराम मिलता है। नमक और पानी लिंफ नोड की सूजन को कम कर देता है। इसके लिए एक कप पानी को हल्का गरम कर लीजिए, उसमें आधा चम्मच नमक मिलाइए। फिर इस पानी से गरारा कीजिए। सूजन कम होने तक दिन में कई बार इसे दोहराएं।

फायदेमंद है लहसुन

लहसुन एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो किसी भी तरह के संक्रमण को आसानी से दूर करते हैं। इसके लिए लहसुन की 2 या 3 कलियों का सेवन कीजिए। खाने में भी लहसुन का प्रयोग कीजिए। अगर समस्या अधिक गंभीर है तो लहसुन के तेल से दिन में 2 या 3 बार मालिश करें। इससे जल्द आराम मिलेगा।

सेब का सिरका

सेब का सिरका लिंफ नोड की सूजन कम करने में के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। यह शरीर के पीएच लेवेल को बढ़ा देता है जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण से भी

बचाते हैं। इसके लिए सेब के सिरके को बराबर मात्रा में पानी से मिलाकर एक कपड़े में को इसमें भिगोकर सूजन वाली जगह पर लगाएं। इसे दिन में दो बार प्रयोग करें। इसके अलावा एक चम्मच सेब का सिरका, एक चम्मच शहद को पानी में मिलाकर सेवन करने से जल्द आराम मिलता है।

बहुत गुणकारी है हल्दी

हल्दी में कई गुण मौजूद होते हैं, इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होता है जिससे किसी भी प्रकार की सूजन आसानी से कम हो जाती है। यह संक्रमण से भी बचाता है और इसके प्रयोग से किसी प्रकार का घाव भी आसानी से और जल्दी भर जाता है। एक चम्मच हल्दी और शहद लेकर अच्छे से मिश्रण बना लीजिए, इसे सूजन वाले हिस्से पर लगाकर 10 मिनट तक रहने दें फिर इसे हल्के गरम पानी से साफ कर लीजिए। दिन में दो बार करने से जल्द आराम मिलता है।

सेहत के लिए फायदेमंद है खुबानी

खुबानी यानी ऐप्रिकॉट एक बीजयुक्त फल है। इस फल में कई प्रकार के विटामन्स और फाइबर होते हैं। खुबानी के बीज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। खुबानी के अनेकों लाभ हैं। खुबानी को न सिर्फ फल के रूप में बल्कि खुबानी के बीज भी इम्यून सिस्टम मजबूत करने में सहायक होते हैं। खुबानी के बीज अवश्य ही खाएं इससे शरीर को ताकत मिलती हैं। आइए जानें खुबानी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में।

पाचन स्वास्थ्य में सुधार- खुबानी फाइबरयुक्त फल है। इससे पाचन तंत्र ठीक होता है। खुबानी खाने से कब्ज संबंधी समस्या दूर होती है। खुबानी कई पाचन संबंधी विकार और बवासीर रोग दूर करने में भी लाभकारी है। खुबानी फल से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। सूखे

खुबानी पेट के लिए लाभकारी हैं।

हृदय स्वास्थ्य में सुधार- खुबानी ऐसा लाभदायक फल है जिससे हृदय संबंधी रोगों से आसानी से निजात पाई जा सकती हैं। खुबानी से कॉलेस्ट्रॉकल नियंत्रित होता हैं।

त्वचा सौंदर्य में बढ़ावा- खुबानी गर्मियों का फल हैं। इसके सेवन से त्वचा में निखार आता है। कील, मुंहासे, त्वचा संक्रमण इत्यादि खुबानी के सेवन से दूर हो सकते है। इतना ही नहीं वर्तमान में उघोग जगत में खुबानी का प्रयोग करके सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं।

कैंसर निरोधी- खुबानी के बीजों में कैंसर निरोधी तत्व मौजूद होते हैं। शोधों में भी यह बात साबित हो चुकी हैं कि खुबानी बीज में पाया जाने वाला विटामिन बी-17 सामान्य कोशिकाओं के लिए पूर्णतया सुरक्षित है और जो कैंसर से बचाव में लाभकारी है।

आंखों को लाभ-खुबानी में प्रचूर मात्रा में विटामिन ए होते हैं। विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट आंखों की कोशिकाओं और ऊतकों के नुकसान की पूर्ति करते हैं। मोतियाबिंद वाले रोगियों के लिए खुबानी उत्तम फल है। खुबानी के बीज से भी आंखों संबंधी समस्याएं दूर होती हैं।

खुबानी के बीज, सूखी खुबानी और खुबानी का रस सभी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं।

हर पल मौत के बीच...

दुनियाभर में ऐसी कई जगहें हैं, जो रहने के लिहाज से बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। हालांकि, इसके बावजूद इन जगहों पर लोग जान जोखिम में डालकर रहते हैं। इनमें से कई जगहें काफी ठंडी हैं, तो कई सबसे ज्यादा प्रदूषित। वहीं, कहीं पर आए दिन ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। आइये जानें दुनिया की ऐसी ही जगहों के बारे में, जहां के लोग हर पल मौत के बीच रहते हैं।

अजब सी वो गंध

दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की ला ओरोया सिटी दुनिया की खतरनाक जगहों में से एक है। यहां की आबोहवा इस शहर को खतरनाक बनाती है। दरअसल, ला ओरोया दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। यहां की हवा में हमेशा अजीब सी दुर्गंध आती है, जिसमें सांस ले पाना बेहद मुश्किल होता है। बावजूद इसके, इस शहर में लगभग 33 हजार लोग रहते हैं।

जानलेवा लावा

ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा पल भर में किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां पर लोग इस तरह के खतरों के बावजूद रहते हैं। ऐसी ही एक जगह इथोपिया का डलॉल है। दरअसल, यहां पर कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, फिर भी लोग वहां रहते हैं। इतना ही नहीं, यहां का तापमान साल भर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। यहां ऊंट के जरिए ही ट्रेवल किया जा सकता है।

पारा माइनस 89.2

धरती की सबसे ठंडी जगह में अंटार्कटिका के वोस्तोक का नाम शुमार किया जाता है। यहां पर रूस का अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन भी है। अगस्त के मौसम में यहां का तापमान सबसे कम हो जाता है। पिछले साल अगस्त में अब तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है।

बचो बिजली से

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के किफुका शहर में रहना तलवार की नोक पर चलने जितना कठिन है। दरअसल, यहां हर साल बिजली गिरने की अनेक घटनाएं होती हैं। यहां हर साल प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 158 से ज्यादा आकाशीय बिजलियां गिरती हैं।

डेथ वैली

डेथ वैली पूर्वी कैलेफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है, जहां पर रहना बेहद ही मुश्किल और खतरनाक है। दरअसल यहां का पारा 60 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद यहां पर लोगों का एक छोटा सा समूह रहता है।

हमसफर पहाड़

चीन के मोतुओ में रहना भी काफी मुश्किल और खतरनाक है। दरअसल, इसकी वजह यहां पर सड़कों का न होना है। ऐसे में लोगों को एक से दूसरी जगह जाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। बावजूद इसके यहां पर 10 हजार से ज्यादा लोग रहते हैं।

खाने के लाले

स्कॉटलैंड के फैरो आइलैंड पर स्थित मूली एक बहुत छोटा सा गांव है। लेकिन यहां पर रहना भी मुश्किल है। दरअसल, यहां पर खाने के लिए न तो सब्जियां हैं और न ही कुदरती संसाधन। इसके बावजूद यहां पर अब भी लोग रहते हैं।

बारिश से तर-बतर

भारत के मेघालय राज्य में पूरे साल मूसलाधार बारिश होती है। ऐसे में यहां पर रहने वाले लोग अपने खान-पान पर कंट्रोल करते हैं और जैसे-तैसे रहते हैं।

सलामांडर की अनोखी क्षमता...

अगर सलामांडर एक्सोलोटल का कोई अंग टूट रहा है तो उसे इस बात की फिक्र नहीं, क्योंकि इस जीव की खासियत है कि इसका अंग शरीर से अलग होने के बाद फिर से आ जाता है। एक्सोलोटल को आप एक तरह की छिपकली कह सकते हैं, जो जलीय जीवों में गिनी जाती है। इस जीव में अंगों के फिर से बनने और स्वयं घाव भरने की अद्भुत क्षमता होती है और तो और नए अंग बनने के बाद इस जीव के शरीर पर किसी तरह का निशान भी बाकी नहीं रहता।

रीढ़ की हड्डी, दिल और दिमाग में गंभीर चोट भी इसी तरह ठीक होती है। एक्सोलोटल के पंगु बनने जैसी कोई घटना नहीं होती। प्रजनन के समय एक्सोलोटल अपने अंग ऊपर उठाकर लहराती हैं। जानवरों के रहने के प्राकृतिक स्थान बढ़ते शहरीकरण और दूषित जल के कारण खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन एक्सोलोटल के अंगो के फिर से बनने की क्षमता के कारण इसके अस्तित्व को फिलहाल कोई खतरा नहीं है।

शोधकर्ता यह जानने के की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सोलोटल में किस तरह से घाव भरने की प्रक्रिया होती है। इसके लिए वे एक्सोलोटल के उत्तकों के जीन अनुक्रम को समझने की भी कोशिश कर रहे है। इस प्रक्रिया के दौरान देखा गया कि एम्ब्लोक्स एंजाइम घाव भरने और अंगों के निर्माण की विधि को गति देता है। कोशिकाओं के साथ किए गए प्रयोग में देखा गया कि एम्ब्लोक्स एंजाइम त्वचा की कोशिकाओं के फिर से बनने में सहायक है।

रेसिपी

फ्रूटी क्रीम चीज

सामग्री

1 कप दूध
1 से 2 टी-स्पून नींबू का रस
2 टेबल-स्पून स्ट्रॉबेरी की प्युरी या आम का पल्प
1 टी-स्पून शक्कर

विधि

दूध को उबालकर 2-3 मिनट तक एक तरफ रख दें। 1 टी-स्पून नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें। अगर दूध पुरी तरह से ना फटे तो एक और चम्मच नींबू का रस डालकर दूध को पुरी तरह फटने दें। दूध से छे पुरी तरह निकल जाना चाहिए। सूती कपड़े से छानकर छे को अलग रख दें। छाने हुए क्रीम चीज़ को मिक्सर में डालकर पीसकर मुलायम पेस्ट बना लें, जहां आप इसे पतला करने के लिए थोड़ा छे मिला सकते हैं। इसे पुरी तरह ठंडा करने रख दें। फल और शक्कर डालकर दुबारा पीसकर मुलायम मिश्रण बना लें। तुरंत परोसें।

कोवालम मटर

सामग्री

1 1/4 कप उबले हुए हरे मटर, 1 टेबल-स्पून तेल, 1/2 टी-स्पून जीरा, 1 टी-स्पून उड़द दाल, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टी-स्पून लहसून की पेस्ट, 1 टी-स्पून धनिया-जीरा पाउडर, 1 टी-स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टी-स्पून हल्दी, 1/2 टी-स्पून बारीक कटा हुआ टमाटर, नमक , स्वाद अनुसार, 1 टेबल-स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पीस कर नारियल-काजू की मुलायम पेस्ट बनाने के लिए (थोड़े पानी का उपयोग करते हुए), 4 टेबल-स्पून कसा हुआ नारियल, 1 टेबल-स्पून टुकड़ा किया हुआ काजू

विधि

एक नॉन-स्टिक कढ़ाई में तेल गरम करिए और उसमे जीरा और उड़द दाल डालिए। जब जीरा चटखने लगे, तब उसमे प्याज डालिए और मध्यम आंच पर 1 से 2 मिनट भूनिए। उसमे लहसून की पेस्ट, धनिया-जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, टमाटर, नमक और 2 टेबल-स्पून पानी डालिए, अच्छे से मिलाइए और मध्यम आंच पर 2 मिनट, बिच-बिच में हिलाते हुए पकाइए। उसमे बनाया हुआ नारियल-काजू के पेस्ट, हरे मटर, धनिया और 1/2 कप पानी डालिए, अच्छे से मिलाइए और मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट, बिच-बिच में हिलाते हुए पकाइए गरमा गरम परोसिए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कांग्रेस की विचारधारा मजबूतः राहुल गांधी

नईदिल्ली । दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं में नया जोश भरा। उन्होंने कहा कि आज के समय में कांग्रेस ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो विचारधारा के स्तर पर मजबूती से खड़ी है और बिल्कुल नहीं टूट रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इसी वैचारिक मजबूती के कारण कांग्रेस ही आरएसएस और भाजपा का मुकाबला करने के लिए सबसे सही और सक्षम पार्टी है।इस बैठक में कांग्रेस के सभी बड़े पदाधिकारी, महासचिव और राज्यों के अध्यक्ष शामिल हुए थे। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने भरोसा जताया कि कांग्रेस आने वाले दो साल में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक मोड़ पर है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कारणों को नहीं, बल्कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।

मणिपुर में फिर हिंसाः दो की मौत, दो घायल

इंफाल। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी नई हिंसक घटना को रोका जा सके। पुलिस के अनुसार, सुबह करीब साढ़े चार बजे अत्याधुनिक हथियारों से लैस हमलावर गांव में घुस आए और ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले के दौरान करीब सात मकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे भारी संपत्ति का नुकसान हुआ।मृतकों की पहचान 35 वर्षीय लेटमिनलुन हाओकिपोप और 23 वर्षीय लुनमिनथांग हाओकिपोप के रूप में हुई है। दोनों कुलतूह गांव के निवासी थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों समुदाय के सक्रिय सदस्य थे। हमले में 28 वर्षीय जांगखोमांग और 27 वर्षीय काममिनलाल घायल हुए हैं। दोनों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की पहचान अभी नहीं हो सकी है।

कोझिकोड में निपाह की दस्तक 77 लोगों की पहचान

तिरुवनंतपुरम (केरल)। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस संक्रमण का एक मामला सामने आया है। इसके साथ ही प्रशासन ने गुरुवार को एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यह संक्रमण कोझिकोड जिले के रामनट्टुकारा के व्यक्ति में पाया गया है। जिला कलेक्टर एमएस माधविकुट्टी ने इसकी पुष्टि की।संपर्क में आए 77 लोगों की पहचान की गई सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मरीज (43 वर्षीय) का इलाज कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। कलेक्टर के मुताबिक, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए 77 लोगों की पहचान की गई है। इनमें 58 स्वास्थ्यकर्मी, 14 परिवार के सदस्य और 5 दोस्त व सहकर्मी शामिल हैं। अभी तक किसी भी संपर्क वाले व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं मिले हैं। इन 77 लोगों में से दो को उच्चतम जोखिम, 13 को उच्च जोखिम और 62 को निम्न जोखिम श्रेणी में रखा गया है।

हमारे पास दो महीने का फुल स्टॉक है : सुजाता शर्मा

नईदिल्ली। पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी पर ईंधन खत्म होने की चिंता सता रही है? अगर हां, तो आपके लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। सरकार ने गुरुवार को उपभोक्ताओं और उद्योगों को आश्वस्त किया है कि आपूर्ति से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं है और पैनिक में आकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। उन्होंने कहा, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की सप्लाई स्थिर है और हमारी रिफाइनरियां अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं। लगातार उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि पिछले तीन महीनों से सरकार यही बता रही है कि देश में पर्याप्त इन्वेंट्री है।

अमेरिकी हमले में दो भारतीय नाविकों की मौत और एक लापता

नई दिल्ली। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एक बेहद दुखद और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां ओमान तट के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में दो भारतीय नाविकों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। इस भीषण हमले के बाद से जहाज के चीफ इंजीनियर भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। समुद्री कंपनियों और यूनियनों के हवाले से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इसमें हुए हताहतों की पुष्टि कर दी गई है। इस हमले का शिकार हुए पलाऊ के झंडे वाले कॉमर्शियल शिप एमटी सेटेबेलो पर कुल 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। खाड़ी क्षेत्र में लगातार गहराते विवाद और बढ़ते सैन्य तनाव के बीच हुई इस हिंसक घटना ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।इस दुखद घटना में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय नाविकों की पहचान हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 23 वर्षीय आदित्य शर्मा और देवरिया, उत्तर प्रदेश के रहने वाले शिवानंद चौरसिया के रूप में हुई है। वहीं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश का घटना के बाद से अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है।

देश में गिरते लिंगानुपात पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गहरी चिंता

जब तक सोच नहीं बदलती, कड़े कानून जरूरी

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में लगातार गिर रहे लिंगानुपात को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। अदालत ने जनगणना के पुराने आंकडों का हवाला देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर बाल लिंगानुपात नीचे जा रहा है। पीठ ने कहा कि साल 1991 में यह आंकडा 945 था जो 2001 में घटकर 927 रह गया। इसके बाद 2011 में यह और भी गिरकर 919 पर पहुंच गया है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने एक डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणियां कीं। अदालत ने इस बात पर दुख जताया कि कई राज्य अभी भी राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक समाज की सोच में बदलाव नहीं आता तब तक पीसीपीएनडीटी अधिनियम को पूरी सख्ती के साथ लागू करने की जरूरत है।

लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण: पीठ ने कहा कि जिस तरह से लिंगानुपात गिर रहा है उससे साफ पता चलता है कि समाज में लडके के प्रति प्राथमिकता अभी भी बनी हुई है। यह स्थिति अवैध तरीके से लिंग चयन की प्रथाओं की मौजूदगी को भी दर्शाती है। अदालत ने कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढाओ और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से भेदभाव मिटाने की कोशिश कर रही है।

पीठ ने आगे कहा कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी सार्वजनिक जगहों पर लडकियों की सुरक्षा और शिक्षा से जुडे विज्ञापन दिखते हैं। यह इस बात का सबूत है कि हालात पहले से बेहतर तो हुए हैं लेकिन अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश बाकी है। सच्ची समानता तभी आएगी जब लडकियों के पैदा होने के अधिकार पर सवाल उठना बंद हो जाएगा।

अदालत ने दिए सांस्कृतिक उदाहरण: अपने फैसले के दौरान उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संस्कृति और साहित्य का भी जिक्र किया। पीठ ने मनुस्मृति के प्रसिद्ध श्लोक यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को उद्धृत किया। इसका अर्थ है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सुभद्रा कुमारी चौहान की मशहूर कविता बालिका का परिचय का भी उल्लेख किया। पीठ ने कहा, कानूनों का सख्त होना तब तक जरूरी है जब तक महिला को कमजोर समझने वाली पुरानी धारणा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती।

डॉक्टर की याचिका को किया खारिज: यह पूरा मामला एक डॉक्टर की अपील से जुडा था। डॉक्टर ने गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के उल्लंघन से जुडे एक मामले में आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर की इस याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिंग चयन और भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को रोकने के लिए कानूनी सख्ती बहुत जरूरी है। अदालत ने कहा कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में लडकियों को जो भेदभाव झेलना पडता है उसे खत्म करना ही न्यायपालिका का उद्देश्य है।

नीट पेपर लीक मामला

खड़गे का मोदी सरकार पर वार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

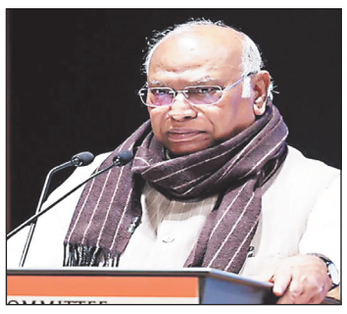

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं ने लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ा है और भारत की परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियों को उजागर किया है। खड़गे की यह टिप्पणी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) में कथित अनियमितताओं को लेकर फिर से शुरू हुई राजनीतिक बहस के बीच आई है। प्रश्न पत्र लीक होने और प्रक्रिया में गड़बड़ी के कई दावों के बाद से ही यह परीक्षा जांच के दायरे में है। इस मुद्दे ने छात्रों और विपक्षी दलों के बीच देशव्यापी चिंता पैदा कर दी है।

इस स्थिति को गवर्नेंस की गहरी चुनौतियों का नतीजा बताते हुए खड़गे ने कहा कि देश की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन सिस्टम की विश्वसनीयता खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार पेपर लीक होने के विवादों ने अहम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के बीच कन्फ्यूज़न, चिंता और अविश्वास पैदा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विवाद की वजह से विरोध-प्रदर्शन और जवाबदेही की राजनीतिक मांगें भी उठी हैं, जिसमें विपक्षी नेताओं ने परीक्षा की सुरक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं।

नीट से जुड़े आरोपों को अधिकारियों - जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी शामिल है - ने लगातार नकारा है या उनकी जांच की है। एजेंसी का कहना है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के उपाय लागू हैं और कथित अनियमितताओं की जांच जारी है। नीट से जुड़ा विवाद एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि परीक्षा में बार-बार होने वाली गड़बड़ियों से भारत की शिक्षा व्यवस्था और लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

खरगे ने बेरोजगारी, परीक्षा में पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे व्यापक मुद्दों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा फिर से कायम करने के लिए सरकार को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। इस बीच, छात्र संगठन और राजनीतिक दल पेपर लीक रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय, तेज़ जांच और भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं।

विपक्षी एकता की आहट : टीएमसी के सौगत रॉय बोले-

भाजपा के खिलाफ कांग्रेस संग मिलकर काम करना जरूरी

नईदिल्ली। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विरोध करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और कांग्रेस पार्टी के बीच संभावित विलय की अटकलों के बीच, सांसद सौगत रॉय ने 11 जून को कहा कि पार्टी के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। रॉय ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि कोई औपचारिक विलय या गठबंधन होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कांग्रेस के साथ काम करना ज़रूरी है। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। हम देखेंगे कि विलय होता है या गठबंधन।

बीजेपी के बारे में बात करते हुए, रॉय ने सत्ताधारी पार्टी पर टीएमसी नेताओं और उनके दफ्तरों के खिलाफ हिंसा करने का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के असर का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की अपील की। ये बातें राज्यसभा में टीएमसी सांसदों के इस्तीफों के सिलसिले के बीच कही गईं। उसी दिन, टीएमसी सांसद प्रकाश चिक बारिक ने ऊपरी सदन से इस्तीफा दे दिया और कहा कि यह फैसला लेने से पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों की राय मानी थी।

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता कीर्ति आज़ाद ने 11 जून को बीजेपी के कथित ऑपरेशन लोटस की आलोचना की। उन्होंने बीजेपी पर सांसदों को पैसे का लालच देने और धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस सांसदों के घरों और दफ्तरों पर मौजूद है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आज़ाद ने लिखा कि अमित शाह की देखरेख में ऑपरेशन लोटस ज़ोरों पर चल रहा है। सूत्रों के ज़रिए कई नाम सामने आ रहे हैं। यह चाल काम नहीं कर रही है। भविष्य के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके पास निश्चित रूप से 16 नाम नहीं हैं। पैसे का लालच दिया गया, धमकाया गया और अब पश्चिम बंगाल पुलिस इन सांसदों के घरों और दफ्तरों पर बैठी है। अमित शाह, थोड़ी और कोशिश कीजिए। आखिरकार, उधार का सिंदूर आपकी मांग में उसी का है, जो कैमरे पर पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था।

अब कल्याण बनर्जी ने ममता को दिया अल्टीमेटम

तृणमूल कांग्रेस में गहराते संकट के बीच, वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी और अपने में से किसी एक को चुनने का अल्टीमेटम दिया है। यह कदम अभिषेक के कथित अहंकारी व्यवहार और कानूनी मामले में अनादर के आरोपों के बाद आया है, जिससे टीएमसी के भीतर गंभीर राजनीतिक कलह उजागर हुई है।

तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रहे संकट को और बढ़ाते हुए कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की आलोचना की है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ। लेकिन ममता दी को यह तय करना होगा कि वह अभिषेक को रखेंगी या मुझे। ममता दी को ही पहले यह तय करना होगा। ममता दी को पहले यह तय करना होगा कि वह अभिषेक बनर्जी के बिना पार्टी नहीं चला सकतीं। तब मैं वहाँ नहीं रहूँगा। कल्याण बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से एक मामले में पेश होने से इनकार कर दिया।

खेल
प्रमुख समाचार

महिला टी20 विश्व कप का आगाज आज से

नईदिल्ली। महिला टी20 विश्व कप का आगाज 12 जून से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाना है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। भारतीय महिला टीम ने अब तक कभी भी टी20 विश्व कप का खिताब नहीं जीता है, लेकिन इस बार वह इसकी प्रबल दावेदार नजर आ रही है।

भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम इस बार काफी दमदार नजर आ रहा है। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना बढ़िया दौर से गुजर रही हैं। इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का रिकॉर्ड इंग्लैंड की धरती पर कमाल का रहा है। इसके साथ ही जेमिमा रोड्रिग्स लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने में माहिर हैं। वहीं, कप्तान हरमनप्रीत कौर अपनी बल्लेबाजी के बूते किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखती हैं। भारतीय टीम के लिहाज से अच्छी बात यह है कि हरमनप्रीत पिछले कुछ मुकाबलों में अच्छी लय में दिखाई दी हैं।

भारतीय टीम को पिछले कुछ समय में टी20 क्रिकेट में मिली सफलता का कारण अंत के ओवरों में ऋचा घोष की तूफानी बल्लेबाजी भी रही है। वनडे विश्व कप में भी उन्होंने अहम मौकों पर लाजवाब पारी खेली थी। इंग्लैंड के खिलाफ हुए अभ्यास मुकाबले में ऋचा ने सिर्फ 36 गेंदों में 68 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। ऋचा अगर इसी फॉर्म को बरकरार रखने में सफल रहीं, तो वह विपक्षी टीम की गेंदबाजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। इंग्लैंड की परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों का रोल काफी अहम माना जाता है। भारतीय टीम के पास इस बार कुछ अच्छी तेज गेंदबाज मौजूद हैं। रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, के साथ-साथ नंदिनी शर्मा ने भी अपनी गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया है। नंदिनी ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही शानदार प्रदर्शन किया था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 150 अंक फिसला निफ्टी 23,162 पर बंद

नईदिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित होने से प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 150.63 अंक यानी 0.20 फीसदी की गिरावट के साथ 73,832.55 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी 53.35 अंक यानी 0.23 फीसदी फिसलकर 23,161.60 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में इंफोसिस, अदाणी पोर्ट एंड स्पेशल इकॉनामी जोन और Eternal सबसे बड़े नुकसान वाले शेयर रहे। व्यापक बाजार में भी दबाव देखने को मिला। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.81 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.67 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए। हालिया तेजी के बाद इन शेयरों में निवेशकों ने मुनाफावसूली की।

150 डॉलर तक जा सकता है कच्चे तेल की कीमत

नईदिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र की चिंताएं बढ़ा दी है। अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद हालात इतने गंभीर नजर आ रहे हैं कि तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़े असर की आशंका जताई जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र की रिसर्च फर्म रिस्टैड एनर्जी के मुताबिक अगर दोनों देशों के बीच टकराव फिर से पूरी तरह शुरू हो जाता है, तो कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी क्षेत्र के छह बड़े तेल उत्पादक देशों में फिलहाल करीब 1.18 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक दौर में यह तेल सप्लाई पर सबसे बड़ा असर माना जा सकता है। तनाव बढ़ने के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत एक समय 94.5 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी।

आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्तवर्ष में घटकर 6.66% रहने का अनुमान

नई दिल्ली। कमजोर निवेश और खपत में वृद्धि के साथ-साथ पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न व्यापारिक झटकों के कारण चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7 प्रतिशत थी। फिच समूह की कंपनी बीएमआई ने यह बात कही। पिछले सप्ताह जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बढ़कर 7.7% हो गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 7.1% थी। यह वृद्धि मजबूत खपत और सशक्त निवेश गतिविधियों के समर्थन से हुई। बीएमआई को उम्मीद है कि चालू कैलेंडर वर्ष में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.1 के स्तर के आसपास कारोबार करेगा। 2025 में 87 के औसत स्तर से रुपए में गिरावट निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी, जिससे ईरान संघर्ष के कारण व्यापार की शर्तों पर पड़े नकारात्मक प्रभाव की भरपाई होगी।

लेंसकार्ट में एक और बड़ी ब्लॉक डील की तैयारी

नईदिल्ली। भारत की प्रमुख आईवियर कंपनी लेंसकार्ट में एक और बड़ी हिस्सेदारी बिक्री की तैयारी चल रही है। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए) के समर्थन वाली प्लैटिनम जैस्मीन ए 2018 ट्रस्ट कंपनी में अपनी करीब 2.3 प्रतिशत हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेचने की योजना बना रहा है। यह डील करीब 1,944 करोड़ रुपए की हो सकती है। हाल ही में जापान के साफ्टबैंक ने लेंसकार्ट में अपनी 3.25 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर करीब 2,873 करोड़ रुपए जुटाए थे। लगातार हो रही बड़ी ब्लॉक डील्स ने निवेशकों का ध्यान एक बार फिर लेंसकार्ट की ओर आकर्षित किया है। बाजार सूत्रों के अनुसार, प्लैटिनम जैस्मीन ए 2018 ट्रस्ट करीब 4 करोड़ शेयर बेच सकता है, जो कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 2.3 प्रतिशत हिस्सा है।

सोने के आयात को रोकने की कवायद के मायने

अश्विनी महाजन

पिछले लगभग तीन माह से अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बाद कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा आने और कीमतों में लगातार वृद्धि होने से देश का आयात-निर्यात का असंतुलन पहले से भी ज्यादा विकट हो गया है। ऐसे में भारतीय रुपया तेजी से कमजोर होकर 95 से 97 रुपए प्रति डॉलर के आसपास चल रहा है और कई विशेषज्ञ तो यह आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं कि यह 100 रुपए प्रति डॉलर की सीमा भी लांघ सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से यह भावुक अपील की है कि वे न केवल पेट्रोलियम पदार्थों के उपभोग को कम करें,

बल्कि विदेशी मुद्रा बचाने हेतु सोने की खरीद को भी कम करें और जरूरत से ज्यादा विदेश यात्राएं भी न करें। हालांकि सोने के आयात पर समय-समय पर आयात शुल्क बढ़ाने से लेकर मात्रात्मक नियंत्रण लगाने तक, कई अंकुश लगाए जाते रहे हैं, लेकिन शायद यह पहली बार है कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने लोगों से सोने की खरीद घटाने के लिए अपील की है।

भारत में लोगों का सोने की खरीद के प्रति आकर्षण कोई नई बात नहीं है। हजारों वर्षों से देश के लोग आभूषणों के रूप में सोने की भारी खरीद करते रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की अपील से कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद प्रधानमंत्री आभूषणों की खरीद पर अंकुश लगाने की अपील कर रहे हैं। क्या आज सोने की सारी मांग आभूषणों के लिए है?

इस संदर्भ में हमें समझना होगा कि पिछले लगभग दो दशकों से देश में आभूषणों के रूप में सोने की खरीद में भारी कमी आई है, फिर भी देश में सोने का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। इस गुत्थी को सुलझाने के

लिए हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों को देखना और समझना पड़ेगा। काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत में कुल सोने का आयात 150 टन रहा,

लेकिन आभूषणों के लिए सोने की मांग सिर्फ 66 टन ही थी। पूर्व में विश्व स्तर पर आभूषण के लिए सोने की मांग 50 प्रतिशत से ज्यादा होती थी, लेकिन यह लगातार घटते हुए वर्ष 2025 तक मात्र 31 प्रतिशत ही रह गई। वर्ष 2025 में पहली बार निवेश के लिए सोने की मांग 2175 टन तक पहुंच गई जो आभूषणों हेतु सोने की मांग से भी ज्यादा थी।

यानी कहा जा सकता है कि देश और विश्व में सोने की मांग इसलिए नहीं बढ़ रही कि स्वर्ण आभूषणों की मांग बढ़ रही है बल्कि इसलिए कि लोग अब सोने को निवेश के रूप में भी रखना चाहते हैं। यही नहीं भारतीय रिजर्व बैंक सहित अधिकांश बड़े देशों के केंद्रीय बैंक भी अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में सोने का अनुपात बढ़ाते जा रहे हैं।

समझा जा सकता है कि सोने के बढ़ते आयात के चलते आज भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ना शुरू हो गया है। परंपरागत स्वर्ण आभूषणों के लिए होने के बजाय अब सोने के आयात ज्यादातर निवेश के लिए होने लगे हैं, इसलिए इस बाबत विचार करना जरूरी है कि लोग निवेश के लिए कुछ अलग प्रकार के उपकरणों का उपभोग करें।

हालांकि भौतिक सोने की खरीद के कुछ नए विकल्प बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन अभी यह व्यवस्था शैशव काल में ही है। लीक से हटकर कुछ नए प्रकार की व्यवस्था के निर्माण की जरूरत है, ताकि लोग भौतिक सोने की खरीद से बचें और उन विकल्पों में निवेश करें, ताकि सोने के मूल्य में वृद्धि का लाभ भी उठाया जा सके और देश में सोने के आयात पर अंकुश भी लग सके।

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रखा विकसित छत्तीसगढ़ का विजन

बस्तर में दूध, खेतों तक पानी, युवाओं को काम और गांवों को नई पहचान देने की तैयारी

दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग कांउसिल की 11वीं बैठक में नक्सलवाद से मुक्त बस्तर की नई तस्वीर देश के सामने रखी। उन्होंने कहा कि दशकों तक हिंसा की मार झेलने वाला बस्तर अब आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और कृषि आधारित विकास का मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में बस्तर के आदिवासी परिवारों की आय दोगुनी करने, दुग्ध क्रांति लाने, 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, पर्यटन को बड़े उद्योग के रूप में विकसित करने तथा एआई और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की व्यापक कार्ययोजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अब नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। वहां दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, खेतों तक पानी पहुंचाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, गांवों में डिजिटल

स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों में बस्तर के परिवारों की मासिक आय बढ़ाकर 30 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में बस्तर के लगभग 85 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। सरकार खेती, पशुपालन, वन उपज, छोटे उद्योग और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में डेयरी मॉडल को तेजी से लागू किया जा रहा है। इसके तहत आदिवासी परिवारों को दुधारू गाय और भैंस उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य गांवों में स्थायी आय का स्रोत तैयार करना है। इस पहल से महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा गांवों में डेयरी केंद्र, दूध संग्रहण, परिवहन और स्थानीय बाजार जैसी नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं से 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इंद्रावती नदी क्षेत्र में सालभर पानी उपलब्ध होने से खेती बेहतर होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसान धान के साथ-साथ सब्जियां, फल तथा अन्य नकदी फसलें भी उगा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगभग 36 लाख लोगों की डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार की जा रही है। इससे मरीजों के इलाज, बीमारी और दवाओं का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा तथा डॉक्टरों को समय पर सही जानकारी मिल सकेगी। इसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगा।

उन्होंने बताया कि बस्तर में बने लगभग 200 सुरक्षा शिविरों को अब सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को राशन, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की 371 योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चित्रकोट और बौद्ध धर्म से जुड़े तीर्थस्थल सिरपुर को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। बस्तर में वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और जंगल सफारी जैसी गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है, जबकि सिरपुर में ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर, संग्रहालय और महानदी तट के विकास पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है। पर्यटकों के आने से होटल, परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प, दुकानदारों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मिलता है। बस्तर को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने से हजारों युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार निवेश, सुशासन और तकनीक आधारित विकास को तेजी से आगे बढ़ा रही है। राज्य में 435 सुधार लागू किए गए हैं और सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत बनाकर निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दो आधुनिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और डिजिटल तकनीक के जरिए विकास का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 100 करोड़ रुपये की लागत से एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है। इसके साथ ही 341 पीएमश्री स्कूल, 5,857 स्मार्ट क्लासरूम और 16 स्थानीय भाषाओं में द्विभाषी पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एग्रीस्टैक योजना के तहत 33 लाख से अधिक किसानों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ा गया है। डिजिटल द्वार प्लेटफॉर्म और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार ने एआई मिशन, पर्यटन मिशन, खेल मिशन, अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप-निपुण मिशन शुरू किए हैं। इन मिशनों से युवाओं को रोजगार, तकनीक और उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे तथा छत्तीसगढ़ को नवाचार और निवेश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत छत्तीसगढ़ में उद्योग, निवेश और निर्यात को नई गति मिली है। खेल सामग्री, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो-एथेनॉल, गारमेंट और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

यातायात व्यवस्था में नया अध्याय माइक्रो बस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ

रायपुर। रायपुर शहर की बढ़ती यातायात समस्या के समाधान और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग और सीईईडब्ल्यू के संयुक्त तत्वावधान में 'माइक्रो बस पायलट प्रोजेक्ट' को हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा, परिवहन सचिव एस प्रकाश और सीईईडब्ल्यू के प्रतिनिधि सौरभ उपस्थित रहे।

पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा यह प्रोजेक्ट इस 45 दिवसीय पायलट प्रोजेक्ट के महत्व को रेखांकित करते हुए सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर की आवश्यकता को देखते हुए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। यह केवल एक ट्रायल नहीं है, बल्कि एक बड़ी कार्ययोजना की शुरुआत है। 45 दिनों के ट्रायल के बाद इस प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे न केवल रायपुर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा।

यातायात सुगम और पर्यावरण के अनुकूल सांसद ने कहा कि रायपुर के भारी ट्रैफिक को देखते हुए ये माइक्रो बसें अत्यंत उपयुक्त हैं। एसी सुविधाओं से लैस ये बसें न केवल नागरिकों को आरामदायक सफर देंगी, बल्कि सड़कों पर व्यक्तिगत वाहनों की संख्या को कम कर ट्रैफिक का दबाव भी घटाएंगी। इससे शहर में जाम की स्थिति से मुक्ति मिलेगी। ऑटो चालकों के लिए भी बढ़ेगा व्यवसाय ऑटो चालकों की चिंताओं पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए सांसद ने कहा कि उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस सेवा के शुरू होने से लोगों का सार्वजनिक परिवहन की ओर रुझान बढ़ेगा। जब लोग अपने निजी वाहन छोड़कर सड़कों पर निकलेंगे, तो वे बसों के साथ-साथ ऑटो का भी उपयोग करेंगे, जिससे अंतत: ऑटो चालकों का व्यवसाय भी बढ़ेगा और शहर की यातायात व्यवस्था सुगम होगी। सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस पहल के सफल होने की कामना की है और रायपुरवासियों से इस आधुनिक परिवहन सेवा को अपनाने की अपील की है ताकि रायपुर को एक %सुगम और स्मार्ट शहर% बनाया जा सके।

राज्यपाल से परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारियों ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक सुब्रत साहू के नेतृत्व में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की।

राज्यपाल श्री डेका ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि अपना कर्तव्य भली-भांति निभाते हुए देश और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें और मानवीय संवेदनाओं के साथ कार्य करें। आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दें साथ ही अपने अधीनस्थों के प्रति भी संवेदनशील रहें।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, संचालक छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी टी सी महावर, प्रशिक्षण निदेशक श्री प्रणव सिंह सहित परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी गोकुल आर. के., वदथ्यवथ यशवंत नाइक एवं इशांत जायसवाल उपस्थित थे।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के मूल्यांकन पर संसदीय स्थायी समिति की रायपुर में बैठक

- कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापार अवसरों पर व्यापक चर्चा

रायपुर। राज्यसभा सांसद एवं वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्ष सुश्री डोला सेन की अध्यक्षता में आज रायपुर के एक निजी होटल में समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक समिति के 10 से 12 जून 2026 तक अहमदाबाद, रायपुर एवं भुवनेश्वर के अध्ययन दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। बैठक में *भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों का मूल्यांकन* विषय पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें व्यापार, निवेश, निर्यात-आयात तथा दोनों देशों के मध्य आर्थिक सहयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। अध्ययन दौरे का उद्देश्य संबंधित हितधारकों एवं अधिकारियों से प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर विषय पर एक व्यापक एवं तथ्यपरक रिपोर्ट तैयार करना है।

बैठक के दौरान कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं एवं निर्यातकों तथा उनके संबंधित उद्योग संघों एवं वाणिज्य मंडलों की क्षेत्रीय शाखाओं के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संघ , अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ , भारतीय खाद्य एवं पेय संघ (आईएफबीए), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया और विषय से संबंधित अपने सुझाव एवं अनुभव साझा किए। समिति द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने, निर्यात संवर्धन तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के वैश्विक बाजार विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

वादा 'विश्वगुरु' बनाने का, लेकिन मिला महंगाई: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भारत को विश्वगुरु बनाने का वादा किया था, लेकिन 12 वर्षों में देश आर्थिक बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और सामाजिक विभाजन जैसी चुनौतियों से घिर गया। जनता के जीवन में बदलाव के सिर्फ प्रचार किया जा रहा है, जबकि लोगों के जीवन में कोई सार्थक बदलाव नहीं आया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने का वादा किया गया था, लेकिन आज हकीकत सामने है और साफ दिख रहा है कि क्या हालात हैं और दुनिया के एक हिस्से में चल रहे युद्ध का भारत पर कितना असर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया, भारत खाद उत्पादन में आत्मनिर्भर होने वाला है, लेकिन सच्चाई यह है कि एलएनजी का उत्पादन 25 प्रतिशत कम हो गया है और यूरिया का उत्पादन काफी हद तक घट गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में वादों के साथ-साथ बड़ी घोषणाएं, बड़े-बड़े बयान और सुर्खियां भी जुड़ी हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव नहीं आया।

भाजपा 2028 में एक दर्जन भी सीटे नहीं जीत पाएगी: शुक्ला

रायपुर। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में हालत खराब है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि समाचार आया है कि भाजपा हारी हुई सीटों पर फोकस करने जा रही है इसके लिए उसने निगम मंडल के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। भाजपा कुछ भी कर ले सारे भाजपा विधायकों के खिलाफ माहौल है तथा अबकी बार भाजपा के सारे मंत्री, विधायक चुनाव हारेंगे और बीजेपी छत्तीसगढ़ में सम्मानजनक विपक्षी दल के रूप में भी नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है अब उसे सारी सीटों में फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी मुश्किल से एक दर्जन सीटे भी नहीं जीतने की स्थिति में है। 2018 विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड फिर से दोहराया जाएगा। प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिछले ढाई साल में भाजपा जनता का भरोसा खो चुकी है। निगम मंडल आयोगों के पदाधिकारियों को शासन के द्वारा जो भत्ता, वाहन, स्टाफ की सुविधा जनता की सेवा के लिए दिया है। उनकी नियुक्ति आयोग मंडलों के गठन जिन उद्देश्यों को लेकर हुआ है उन जनकल्याणकारी कामों को पूरा करने के लिए हुआ है।

5 नये मेडिकल कॉलेज मान्यता पर एनएमसी ने लगाई रोक: ठाकुर

रायपुर। पांच नये मेडिकल कॉलेज खोलने पर एनएमसी की रोक के लिए स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार पांच नये मेडिकल कालेज खोलने को लेकर गम्भीर नही थी। कांग्रेस सरकार ने दिसम्बर 2022 में कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बिल्डिंग एवं अस्पताल और अन्य मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने फंड भी स्वीकृत किया गया था लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार दो साल तक कॉलेज बिल्डिंग एवं अस्पताल भवन बनाने टेंडर की प्रक्रिया ही शुरू नहीं की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने गृह जिला जशपुर के कुनकुरी में मेडिकल कालेज बनाने की घोषणा की वहां भी अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज के लिए विकास कार्य शुरू नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल कॉलेज खोलने के तय मापदंडों को पूरा करने में रुचि नहीं दिखायी। बल्कि एनएमसी को मेडिकल कॉलेज के लिए बिल्डिंग एवं अस्पताल के सम्बंध में गलत जानकारियां दी गई। जिसे एनएमसी ने सैटेलाइट निरीक्षण के पश्चात गलत पाया और पांचों नये मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं दी।

डीएड अभ्यार्थियों के संबध में सरकार हठधर्मिता छोड़ें: वंदना

रायपुर। कांग्रेस ने मांग किया कि सरकार डीएड अभ्यर्थियों की मांग पर मानवीय रवैया अपनाते हुये तत्काल इनकी नियुक्ति आदेश निकाले प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि डीएड अभ्यर्थी अपनी जायज मांग के लिये लड़ाई लड़ रहे तथा अदालत वे उनकी नियुक्ति के संदर्भ में आदेश है इनकी मांगो पर निर्णय नही लेना सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर भी सवाल खड़ा करता है। सरकार ने इनकी नियुक्ति के लिये बीएड चयनित लोगों को बर्खास्त भी किया था तथा उनका समायोजन भी कर दिया है फिर इनके संबध में निर्णय में विलंब क्यो हो रहा है ?डीएड अभ्यर्थियों सहायक शिक्षकों की 2300 से अधिक पद नियुक्ति की मांग को लेकर माना तूता धरना स्थल पर भरी गर्मी में 169 दिनों से आंदोलन पर है। लंबे समय से चल रहे आंदोलन के कारण अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। मानसिक तनाव एवं खुले में रात-दिन आंदोलन करने के कारण मौसम का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आंदोलनकारियों की तबियत खराब हो रही है। आंदोलनकारियों ने सरकार तक अपनी बात पहुँचाने जल सत्याग्रह, अंगार में चलना, दण्डत्व यात्रा, मुख्यमंत्री निवास घेराव सहित नाना प्रकार के प्रदर्शन कर चुके है।

युक्तियुक्तकरण के नाम पर हजारों स्कूल बंद: वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों के बढ़ते ड्रॉपआउट रेट के लिए सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार की दुर्भावना के चलते ही प्रदेश के साढ़े तीन लाख से अधिक बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने मजबूर हुए हैं। भाजपा सरकार ने विगत शिक्षण सत्र के दौरान ही 10463 स्कूल बंद कियेए उन स्कूलों का डायस कोड़ मर्ज कर दियाए नए सेटअप के नाम पर सभी 56895 सरकारी स्कूलों में शिक्षक के न्यूनतम पदों की संख्या में कटौती करके नियमित शिक्षकों के 56,895 पदों को समाप्त कर दियाए छात्र शिक्षक अनुपात बढ़ाए, हर महीनें हजारों शिक्षक सेवानिवृत हो रहे हैं, लेकिन यह सरकार नई भर्ती नहीं कर रही है, उल्टे रिमोट एरिया में सीमित संसाधनों से वर्षों से सेवा दे रहे विद्या मितान, अतिथि शिक्षकए प्लेसमेंट और संविदा शिक्षकों को भाजपा सरकार आने के बाद नौकरी से निकाला गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यह सरकार नहीं चाहती कि गरीब बच्चों को नि:शुल्क और उत्कृष्ट शिक्षा मिल सके। भाजपा की सरकार में शिक्षा विभाग वसूली गिरोह की तर्ज पर चल रहा है।

डिजिटल भू-अभिलेखों की सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम

ई-एचआरएमएस पोर्टल से रखी जाएगी नजर

- राजस्व मंत्री का कड़ा रुख : 15 अगस्त तक पूरा करें नगरीय पट्टा वितरण सर्वे
- 3 साल से जमे तहसीलदारों व पटवारियों की सूची तलब

रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने आज अपने निवास कार्यालय में विभाग के आला अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में आम जनता को राहत देने और शासकीय योजनाओं में तेजी लाने के लिए मंत्री श्री वर्मा ने कड़े तेवर दिखाते हुए कई बड़े फैसले किए। इस बैठक में सचिव सुश्री शम्मी आबिदी, संचालक श्री विनीत नंदनवार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।जमीन संबंधी रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या साइबर खतरे को रोकने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। बैठक में मंत्री श्री वर्मा ने डिजिटल भू-अभिलेखों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए एक अभेद्य कार्ययोजना तैयार करने की बात कही, जिससे जनता का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे।

राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को ट्रैक करने के लिए एसईसीएल पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर उनकी पदस्थापना, अवकाश, विभागीय जांच, गोपनीय प्रतिवेदन और अचल संपत्ति की पूरी जानकारी हर वक्त अपडेट रहेगी।

राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्री श्री वर्मा ने प्रदेश भर के जिलों में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक/सहायक अधीक्षक और राजस्व निरीक्षकों की सूची तलब की है. इसके साथ ही, एक ही हल्का में 3 साल से ज्यादा समय से जमे पटवारियों का भी पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और पात्र हितग्राहियों को पट्टा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने समय-सीमा तय कर दी है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि नगरीय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण करने हेतु सभी आवश्यक सर्वे कार्य आगामी 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से पूरे कर लिए जाएं, ताकि समय पर उन्हें मालिकाना हक मिल सके। बैठक में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने शासकीय जमीनों के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन शासकीय भूमियों की लीज समाप्त हो चुकी है, तत्काल नवीनीकरण की प्रकिया हेतु संबंधित को सूचित किया जाए। इसके साथ ही, शासन द्वारा लीज पर दी गई जमीनों की समीक्षा कर नियमों के तहत उचित शुल्क निर्धारण करने को कहा गया, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।एजेंडे में जमीन आबंटन, आकाशीय बिजली से बचाव, रायगढ़ के घरघोड़ा में एसईसीएल भू-अर्जन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

देशभर में सरकार के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन

रायपुर/दिल्ली। महंगाई, पेपर लीक, सीट चोरी, बेरोजगारी, खाद-बीज, आर्थिक मंदी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस देशभर में आक्रमक प्रदर्शन की तैयारी में है. दिल्ली में आयोजित एआईसीसी की बैठक में आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और आंदोलन की रणनीति बनाई गई.

- महंगाई, पेपर लीक, सीट चोरी, बेरोजगारी का उठाएंगे मुद्दा, एआईसीसी की बैठक में बनी रणनीति

राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमुख्यालय इंदिरा भवन में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय महासचिवों के साथ प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों की मौजूदगी रही. बैठक में राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई अन्य नेता मौजूद थे.छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि महंगाई, पेपर लीक एवं किसानों की समस्याओं को लेकर ब्लॉक स्तर लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आक्रमक प्रदर्शन किया जाएगा. आज पार्टी की बैठक में देश में जो हालात हैं उस पर विस्तार से चर्चा हुई. बैज ने कहा कि एआईसीसी से निर्देश मिलने के बाद भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा. उन्होंने कहा, भाजपा लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.